हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

20 जनवरी, 1998

(प्रथम बैठक)

खण्ड-1, अंक-2

अधिकृत विवरण

विषय सूची

मंगलवार, 20 जनवरी, 1998

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(2) 1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(2) 17
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(2) 20
स्थगन प्रस्ताव की सूचना	(2) 23
वाक आउट	
नियम 121 के अधीन प्रस्ताव	(2) 24
स्थगन प्रस्ताव की सूचना (पुनरारम्भ)	(2) 24
वैयक्तिक स्पष्टीकरण -	
श्री ओम प्रकाश चौटाला द्वारा	(2) 25
स्थगन प्रस्ताव की सूचना (पुनरारम्भ)	(2) 26
नियम 121 के अधीन प्रस्ताव (पुनरारम्भ)	(2) 26
वर्ष 1997-98 के अनुपूरक अनुमान पेश करना	(2) 28
वर्ष 1997-98 के अनुपूरक अनुमानों पर एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट पेश करना	(2) 29
वर्ष 1998-99 (चार मास) का लेखानुदान पेश करना	(2) 28

मूल्य : 56 00

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 20 जनवरी, 1998

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (प्रो० छत्तर सिंह चौहान) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : साहेबान अब सवाल होंगे।

Providing of free Ambulance Facility

***478. Shri Dev Raj Dewan** ; Will the Minister for Health be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to provide Ambulance facility free of cost to the poor patients in Civil Hospital, Sonipat ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश महाजन) : जी नहीं।

श्री देवराज दीवान : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के द्वारा "जी नहीं" कहने से कैसे गुजारा चलेगा क्योंकि बहुत से गरीब आदमी सिर्फ एम्बूलैन्स न मिलने की वजह से ही मर जाते हैं। उनको इसके अभाव में रोहतक मैडीकल कालेज या दिल्ली होस्पीटल में नहीं पहुंचाया जा सकता। सरकार की तरफ से उनको कोई भी एम्बूलैन्स का इंतजाम नहीं करवाया जाता। वहां पर केवल रेडक्रास की एक एम्बूलैंस होती है जोकि अक्सर अफसरों के पास ही रहती है जिस कारण वह उन गरीब मरीजों के कोई काम नहीं आती।

श्री अध्यक्ष : आप सवाल पूछिए।

श्री देवराज दीवान : सर, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इनका वहां पर एम्बूलैंस उपलब्ध करवाने का कोई विचार है ?

श्री ओम प्रकाश महाजन : अध्यक्ष महोदय, इनके अपने सोनीपत क्षेत्र में चार एम्बूलैंस हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि अपने हरियाणा स्टेट में 67 एम्बूलैंस सैंट जोंस एम्बूलैंस सोसायटी के द्वारा रेडक्रास के माध्यम से चलती हैं। इनके क्षेत्र में तो चार एम्बूलैंस हैं तथा वहां पर कोई भी इस प्रकार का मरीज नहीं है जिसको एम्बूलैंस उपलब्ध न करवायी जाती हो। चाहे सीरियस मरीज है या अननोन हो जो भी मरीज जहां जाना चाहता है, उसको वे एम्बूलैंस वहां पहुंचा देती हैं।

श्री देवराज दीवान : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात का साक्षात प्रमाण हूं कि किसी भी गरीब आदमी को वहां एम्बूलैंस नहीं मिलती। होस्पीटल में कह देते हैं कि पहले चार सौ रुपये जमा करवाओ तब आपको एम्बूलैंस मिलेगी। वैसे तो वे आम तौर पर कह देते हैं कि ड्राईवर नहीं है या एम्बूलैंस नहीं है। सर, आप यह बात होस्पीटल से पता कर सकते हैं और इसकी इंक्वायरी करवा सकते हैं।

श्री ओम प्रकाश महाजन : अध्यक्ष महोदय, रेडक्रास के माध्यम से सैंट जोंस सोसायटी की जो एम्बूलैंस चलती है वह डी०सी० की चेयरमैनशिप में चलती है। जिस गरीब आदमी की जांच करके यह पाया जाता है कि वह गरीब है तो उसको ये एम्बूलैंस फ्री दी जाती है लेकिन जो मरीज गरीब नहीं होते हैं उनसे इनकी पेमैंट ली जाती है और जो आदमी पेमैंट अदा करता है उसको फौरन ये एम्बूलैंस मिल जाती है।

श्री भागी राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो सीरियस मरीज होगा क्या वह पहले डी०सी० को एम्बुलैंस के लिए दरख्वास्त देगा या फिर डी०सी० उसकी इंक्वायरी करेगा कि वह गरीब है या नहीं ? अध्यक्ष महोदय, डी०सी० कितने दिनों के अन्दर उसकी इंक्वायरी करके उसको फ्री एम्बुलैंस की सुविधा देगा ? अगर वह ज्यादा दिन लगाएगा तो क्या तब तक वह मरीज जिंदा रहेगा ? जो गरीब आदमी है और सीरियस बीमार हैं एम्बूलैंस तो उन्हीं को चाहिए।

श्री ओम प्रकाश महाजन : अध्यक्ष महोदय, ऐसा प्रावधान नहीं है। जब कोई सीरियस मरीज होता है तो उस समय डी०सी० नहीं बल्कि होस्पीटल के एम०ओ० को यह पावर है कि वह फौरन उस मरीज को एम्बूलैंस में भेज दें और अस्पताल शिफ्ट कर दें। उस आदमी की जांच बाद में हो जाती है।

श्री भागी राम : अध्यक्ष महोदय, पहले पैसा भरवाते हैं और फिर उसको एम्बूलैंस देते हैं।

श्री ओम प्रकाश महाजन : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताया है कि जो गरीब आदमी हैं या जो सीरियस बीमार होते हैं उनके लिए यह जरूरी नहीं कि एम्बूलैंस लेने के लिए पहले डी०सी० से ऐप्रुवल लें और फिर उनको एम्बूलैंस दें। जो मरीज सीरियस है या अननोन है उसको होस्पीटल का एम०ओ० ही एम्बूलैंस दे सकता है। उसकी ऐप्रुवल गरीबी के कारण दी जाती है और डी०सी० से ऐप्रुवल बाद में आ जाती है। अगर वह मरीज गरीब नहीं है तो उसकी पेमैंट आ जाती है।

श्री भागी राम : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह था कि उससे पहले पैसे भरवाए जाते हैं या नहीं ? इसका माननीय मंत्री जी जवाब दें ?

श्री ओम प्रकाश महाजन : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कह दिया है कि जो गरीब आदमी पैसे उस वक्त नहीं दे सकता तो उससे कोई पैसा नहीं भरवाया जाता।

Introduction of English Subject

***489. Dr. Virender Pal Ahlawat :** Will the Minister for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to introduce the subject of English from Ist standard in Government schools in the State.

शिक्षा मन्त्री (श्री राम बिलास शर्मा) : जी नहीं ।

डॉ० वीरेन्द्र पाल अहलावत : अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां गांव या शहरों के वे आदमी जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में मात्र इसलिए पढ़ाते हैं कि वे प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से तय की गई फीस नहीं दे पाते। क्या यह उनके बच्चों के अधिकारों का हनन नहीं है क्या उन्हें शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाता ? चाहे किसी गांव के अंदर किसी ने प्राइवेट स्कूल खोल रखा है उनके यहां भी

पहली क्लास से अंग्रेजी पढ़ाई जाती है जबकि हमारे यहां सरकारी स्कूलों में 20-20 कमरे होते हैं पी०एच०डी० और एम०फिल० किए हुए शिक्षक जे०बी०टी० टीचर लगाए जाते हैं और वे प्राइवेट स्कूलों से कई गुणा ज्यादा तनख्वाहें ले रहे हैं। जब प्राइवेट स्कूलों में अंग्रेजी पहली क्लास से पढ़ाई जा सकती है तो सरकारी स्कूलों में पढ़ाए जाने में क्या समस्या है, इस बारे में कृपया शिक्षा मंत्री जी बताएं ?

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, संस्कार जगत और शिक्षा जगत में एक मान्यता है कि बच्चे का पहला विकास मां के दूध की भाषा में होना चाहिए। इसलिए हिन्दुस्तान के सराउंडिंग में अंग्रेजी विषय को पहली कक्षा से पढ़ाया जाना हम अवैज्ञानिक मानते हैं इसके ऊपर हमने काफी विचार विमर्श किया और कुछ प्रान्तों ने इसे प्रारंभ भी किया जिसके अच्छे परिणाम नहीं आए। माननीय साथी का कहना ठीक है कि राजकीय विद्यालयों में अच्छे स्तर के अध्यापक हैं, पी०एच०डी० किए हुए अध्यापक हैं। लेकिन अंग्रेजी विषय का जो तुलनात्मक अध्ययन किया गया है, वह यह है कि इससे बच्चों पर अत्यधिक भार पड़ता है और उनके मानसिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है हिन्दुस्तान का बच्चा हिन्दी में ही सोचता है और उसे हिन्दी में ही अभिव्यक्त करता है और जबरदस्ती ऐसा करने से उसके मौलिक विकास में बाधा आती है। पहली कक्षा से अंग्रेजी पढ़ाने हेतु हमने ऐक्सपैरीमैंट भी किया था लेकिन उससे ड्रॉप आउट की संख्या बढ़ गई थी इसलिए पहली कक्षा से अंग्रेजी पढ़ाए जाने को हम उचित नहीं मानते।

डॉ० वीरेन्द्र पाल अहलावत : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय पहली कक्षा से अंग्रेजी विषय पढ़ाने को अवैज्ञानिक मानते हैं। पता नहीं उन्हें विज्ञान का ज्ञान नहीं है या क्या बात है ? क्या इस प्रदेश के अंदर प्राइवेट स्कूलों को पहली कक्षा से अंग्रेजी पढ़ाए जाने के लिए रीकग्नाइज नहीं किया गया, यह असमानता क्यों है? यदि ऐसा है तो क्या आप इसे डी-रीकग्नाइज करने जा रहे हैं ? पता नहीं अंग्रेजी भाषा सीखने में मौलिकता कहां गुम हो जाती है। प्राइवेट स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ाने से मौलिकता बढ़ जाती है और सरकारी स्कूलों में पढ़ाने से मौलिकता घट जाती है यह मेरी समझ से बाहर है। क्या मंत्री जी इस बारे में बताने की कृपा करेंगे ?

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मित्रों को फोबिया हो गया है। मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि माननीय सदस्य ने सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी पढ़ाए जाने बारे सवाल पूछा था। जहां तक मौलिक विकास की बात है वीरेन्द्र पाल जी ने तो डंगरों वाले विषय में डॉक्टरेट किया है। मैंने तो विद्यालय में पढ़ाया है लेकिन डॉ० वीरेन्द्र पाल जी तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट करके आये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं उनको बताना चाहता हूं कि अंग्रेजी पढ़ाने के हम विरोधी नहीं हैं तथा किसी भी विद्यालय को जब हम मान्यता देते हैं तो उस विद्यालय का माध्यम नहीं देखते सिर्फ उस विद्यालय के नार्म्स के हिसाब से मान्यता देते हैं। परन्तु अध्यक्ष महोदय, दुनिया में 49 करोड़ आदमी ऐसे हैं जिनकी मात्र भाषा हिन्दी है और 39 करोड़ आदमी ऐसे हैं जिनकी मात्र भाषा अंग्रेजी है तथा हिन्दी पढ़े हुए आदमी आज भी इंगलैंड, अमेरिका, कनाडा में वेस्ट टेलैंटिड, हॉर्ट स्पेसलिस्टस, इंजीनियर्स हैं उनमें भारतीय मूल के लोगों की संख्या 80 प्रतिशत है। स्पीकर सर, हमारी मान्यता यह है कि बच्चे को प्राथमिक स्तर पर उसकी मां के दूध से बच्चे को जो भाषा सुनने को मिलती है उसी भाषा में उसको शिक्षा दी जाये उसी से उसका विकास होता है अगर उससे अतिरिक्त कोई भाषा उस बच्चे पर थोप दी जाती है तो उससे बच्चे का मानसिक विकास रूक जाता है उसके मस्तिष्क को दो-तीन गुणा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कुछ बच्चे इस अतिरिक्त बोझ को वहन नहीं कर पाते और उनके मानसिक विकास में रूकावट आ जाती है। नालन्दा, तक्षशिला विश्वविद्यालयों में जो शिक्षक रहे वे हिन्दुस्तान से ही रहे हैं मैं डॉ० वीरेन्द्र पाल को बताना चाहता हूं कि (विघ्न)

डॉ० वीरेन्द्र पाल अहलावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यह तो ठीक है कि इन्होंने विद्यालय में ही पढ़ाया है लेकिन हमारे यहां जितने भी हिन्दी भाषा के ठेकेदार बनते हैं क्या उनके बच्चे इंग्लिश माध्यम के विद्यालयों में नहीं पढ़ते ? उनका पूरा परिवार जिसमें जितने बच्चे पढ़ने वाले होते हैं वे सब आज यहां चण्डीगढ़ के इंग्लिश माध्यम के स्कूलों में पढ़ रहे हैं क्या उन बच्चों की नैतिकता खराब नहीं होती ? शिक्षा मंत्री जी मेरे से ज्यादा मनोवैज्ञानिक होंगे लेकिन यह बात मेरी समझ से बाहर है। यह उन लोगों के साथ ज्यादती है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि हरियाणा के विद्यालयों में पहली क्लास से अंग्रेजी विषय शुरू किया जाये।

श्री राम बिलास शर्मा : मैं तो दस किलोमीटर पैदल चलकर विद्यालय में पढ़ने जाता था।

डॉ० वीरेन्द्र पाल अहलावत : आपकी नहीं यह बच्चों की बात है।

श्री राम बिलास शर्मा : मेरे बच्चे आज भी हिन्दी माध्यम में डी०ए०वी० स्कूल में पढ़ रहे हैं दूसरी मनोवैज्ञानिक की जो बात है, स्पीकर सर, मैं तो पांच हजार साल पहले के इतिहास की बात कह रहा हूं। दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए, एलिमेंटरी नौलेज के दशमलव, गिनती के चाहे दूसरी भाषा के रहे हों परन्तु जर्मनी के विद्वान ने कहा है कि दुनिया यह मानती है कि भारत के वेद बहुत उपयोगी हैं। यहां तक कि अमेरिका की एक संस्था ने रिसर्च किया है कि अणु के बारे में अनुसंधान रूक गया था तब वेदों की सहायता से उसे आगे प्रारम्भ किया गया। अगर अहलावत जी अंग्रेजी के बारे में ज्यादा कोशिश करते हैं हमें नार्म्ज बता दें हम इसे प्रारम्भ कर देंगे। परन्तु राजकीय विद्यालयों में अंग्रेजी का विषय शुरू करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है।

डॉ० वीरेन्द्र पाल अहलावत : हमारे शहरों में सरकारी विद्यालयों में हरिजनों के बच्चे केवल वजीफा लेने के लिए ही पढ़ते हैं और वहां नाम लिखवाते हैं उनको इतनी सुविधाएं दी जाती हैं इसके बावजूद वे फायदा नहीं उठा पाते। अगर ऐसा कुछ नहीं किया जाता है तो हमें शिक्षा मंत्री महोदय के बताए हुए रास्तों पर ही चलना पड़ेगा। हमारी मजबूरी है।

श्री अध्यक्ष : डॉ० वीरेन्द्र पाल जी, हम और आप बाई-चांस ही अंग्रेजी सीख गए हैं। क्या आप बताएंगे कि हमारी सोच अंग्रेजी की है या हिन्दी की है ?

डॉ० वीरेन्द्र पाल अहलावत : अध्यक्ष महोदय, यह तो अभिव्यक्ति की बात है।

श्री अध्यक्ष : अभिव्यक्ति तो मातृभाषा में अधिक आसानी से हो सकती है।

डॉ० वीरेन्द्र पाल अहलावत : अध्यक्ष महोदय, किसी भाषा का ज्ञान होना मातृभाषा का विरोध नहीं है। आप जितनी मर्जी भाषाएं सीख सकते हैं, इस बात का विरोध नहीं होना चाहिए।

श्रीमती करतार देवी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया है, इसमें बुनियादी तौर पर एक बात है कि प्रदेश के सभी बच्चों को समान शिक्षा का अधिकार हो। मेरे माननीय भाई बहुत ही काबिल हैं लेकिन जिस ढंग से इस बात को पीछे हटाया जा रहा है, वह ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं तो एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूं कि मॉडर्न स्कूल, रोहतक में सभी अधिकारियों के बच्चे पढ़ते हैं तथा उनको वहां अपने बच्चों को दाखिला दिलवाने में कोई खास दिक्कतें नहीं आती हैं। लेकिन दूसरी ओर, सामान्य आदमी के बच्चों को वहां पर दाखिला लेने के लिए जबरदस्त प्रतियोगिताओं से गुजरना पड़ता है और सिफारिशें भी ढूंढनी पड़ती हैं। यह मौलिकता उन अधिकारियों के बच्चों पर लागू नहीं होती है। ठीक है, अभी यह बात वहां लागू नहीं है, लेकिन जैसे कि हमारे शिक्षा मंत्री बहुत ही योग्य और

काबिल हैं इसलिए उनसे आग्रह है कि क्या समान शिक्षा का अधिकार दूसरे बच्चों को नहीं होना चाहिए ताकि एक ही विद्यालय में एक चीफ इंजीनियर का लड़का भी और एक सफाई करने वाले का बच्चा भी एक साथ पढ़ सकें जिससे कि उनका विकास एक साथ हो सके। क्या जिला या ब्लाक स्तर पर ऐसे स्कूल खोलने के लिए कोई प्लान बनाई जाएगी जैसे कि इस बारे में पीछे भी कहा गया था ?

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, बहिन जी ने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। हमने पिछले साल हर जिले में एक आदर्श विद्यालय का प्रयोग किया है। इसके लिए जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं और उन में से भी खास तौर पर से जो विज्ञान के विद्यार्थी होते हैं, उन आठवीं, दसवीं और 10+2 के विद्यार्थियों के लिए एक्सट्रा कोचिंग के लिए भी हम ने प्रबन्ध किया है। दूसरी बात जहां तक प्राइवेट विद्यालयों द्वारा महंगी शिक्षा देने के बारे में है, यह बात सही है कि उनकी फीसें ज्यादा हैं और उन विद्यालयों में एक गरीब आदमी अपने बच्चों को दाखिल नहीं करा सकता है। इस बारे में हमने पिछले साल प्रदेश स्तर पर एक कमेटी बनाई थी और जहां-जहां पर फीस के बारे में शिकायतें आई थीं, कमेटी ने संबंधित विद्यालयों को इस बारे में निर्देश दिए हैं और आगे आने वाले सत्र में हम इन विद्यालयों में अनुसूचित जाति और अन्य वर्गों के बच्चे जो सभी कंडीशंज़ पूर्ण करते हैं, को दाखिला देने का प्रावधान करने जा रहे हैं।

श्रीमती करतार देवी : अध्यक्ष महोदय, मैंने बच्चों को समान शिक्षा देने के लिए माननीय मंत्री जी से पूछा है कि इसके बारे में सरकार का क्या विचार है ?

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक समान शिक्षा की बात है इसके लिए राजकीय विद्यालयों का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, एक बात यह भी आई कि सरकारी स्कूलों में तो केवल हरिजनों के बच्चे ही पढ़ते हैं, यह बात ठीक नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश के विद्यालयों में 24 लाख छात्र पढ़ते हैं और इसी सदन में पिछले सत्र में सभी माननीय विधायकों ने कहा था कि स्कूलों का दर्जा बढ़ाया जाए, इसलिए इनकी मांग के अनुसार हम ने स्वर्ण जयंती वर्ष में 375 विद्यालयों का दर्जा बढ़ाया है। (शोर) चौधरी धीरपाल जी व बलवंत सिंह मैना जी के हल्कों में स्कूलों का दर्जा बढ़ाया है। पूरे 90 विधान सभा क्षेत्रों में स्कूलों का दर्जा बढ़ाया है। (शोर) अब बात कह कर बात से फिर जाना है, तो हम क्या कर सकते हैं ? (शोर) चौधरी धीरपाल जी और बलवंत सिंह मैना जी से पूछा जा सकता है कि उनके यहां स्कूलों का दर्जा बढ़ाया है अथवा नहीं।

डॉ० वीरेन्द्र पाल अहलावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि मेरे हल्के में बेरी व चिमनी के विद्यालयों का दर्जा नहीं बढ़ाया गया है (शोर)

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, एक आध स्कूल अगर दर्जा बढ़ाने से रह भी गया है तो इस साल उसका दर्जा बढ़ा देंगे। (शोर)

डॉ० वीरेन्द्र पाल अहलावत : मैं शिक्षा मंत्री महोदय से इतना ही पूछना चाहूंगा कि क्या जिले के अन्दर एक स्कूल को मॉडल स्कूल बनाने से जिले की समस्या हल हो जाएगी ? मॉडल स्कूल उन स्कूलों को बनाया गया है जिनमें वहां के अध्यापकों के या वहां के प्रिंसिपल या मुख्याध्यापक के प्रयासों से पहले ही रिजल्ट सैन्ट परसैन्ट आते थे। वहां पर न सिर्फ इन स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाया गया है बल्कि वहां के प्रिंसिपल के कहने से सब बढ़िया से बढ़िया अध्यापक उन स्कूलों में लगाए गए हैं। इस प्रकार असमानता लाने के बजाए जब तक हरियाणा के छोटे से छोटे गांव या हर स्कूल का विकास नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा यह केवल ढकोसला है और लोगों को दिखाना है कि कुछ कर रहे हैं।

श्री राम बिलास शर्मा : मेरे माननीय साथी अपने सवाल से हट गए। वे मानते हैं कि हमने हरियाणा में आदर्श विद्यालय स्थापित किए। इन्होंने माना है कि जिन स्कूलों के रिजल्ट अच्छे हैं उनको आदर्श विद्यालय बनाया। हमारी आलोचना करें यह उनका अधिकार है। परन्तु शिक्षा जगत में पिछले एक साल से जितने स्कूलों का स्तर बढ़ा है, जब से हरियाणा बना है तब से लेकर आज तक उतने विद्यालयों का स्तर नहीं बढ़ा है। जहां तक आदर्श विद्यालयों की बात है, यह प्रयोग हमने जानबूझ कर किया है कि सरकारी विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ते हैं उन को आगे आने का अवसर मिलें, उनको कोचिंग मिले। पिछली बार 10वीं, 12वीं के परिणामों में सरकारी स्कूलों की बात है। कई वर्षों के बाद 10वीं, 10+2 में सरकारी स्कूलों के बच्चे प्रथम स्थान पर आए। जहां तक सबको समान शिक्षा का अधिकार है, आप खुद मानते हैं कि सरकारी विद्यालयों में ज्यादा शिक्षित अध्यापक हैं, ज्यादा प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए अध्यापक हैं तो यह समान शिक्षा के लिए ही तो प्रावधान किया गया है। समान शिक्षा के कारण ही सरकारी विद्यालयों में मैक्सिमम छात्र/छात्राएं हैं। इस समय 24 लाख छात्रों की संख्या है। पिछले साल 7 लाख छात्रों की संख्या बढ़ी है। पिछले साल 10+2 का रिजल्ट 11 प्रतिशत बढ़ा। 10वीं का रिजल्ट 14 प्रतिशत बढ़ा और 8वीं का 11 प्रतिशत बढ़ा। स्पीकर सर, आप जानते हैं परीक्षा परिणाम लगातार 2-3 वर्षों की मेहनत से बढ़ें हैं। इस साल एक्स्ट्रा कोचिंग 8वीं, 10वीं और 12वीं को हम सरकारी विद्यालयों में कर रहे हैं डॉ० साहब उसमें सहयोग करें।

स्पीकर सर, मैं माननीय साथी को बताना चाहता हूं कि पूरी दुनिया के शिक्षाविदों की राय है कि पहली कक्षा में मात्र मातृ भाषा में बच्चे को जानकारी देनी चाहिए। इसलिए पहली कक्षा में अंग्रेजी शिक्षा प्रारम्भ करने का हमारा कोई विचार नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय शिक्षा मंत्री आज गांवों में और शहरों में भी शिक्षण संस्थाओं के व्यापारीकरण की प्रवृत्ति दिनों दिन बढ़ती जा रही है। क्या सरकार इसकी तरफ कोई कदम उठाने का विचार कर रही है ?

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आप ने ठीक फरमाया। पिछले साल हमारे पास अनेक स्थानों से इस तरह की शिकायतें मिलीं। हमने प्रदेश के डी०एस०ई० की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाई। उस कमेटी ने हर जिले की इस तरह की शिकायतों की जांच की। जिन लोगों ने इसे व्यवसाय के नाते लिया हुआ है आने वाले समय में हम इस पर कारगर कदम उठाएंगे।

तारांकित प्रश्न संख्या 515

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला सदन में उपस्थित नहीं थे)

Development of National Highways

***494 Shri Krishan Lal :** Will the Minister for PWD B & R be pleased to state whether the State Government has sent any proposal to the Government of India in the year 1996-97 for the maintenance/strengthening of the National Highways passes through the State of Haryana; if so, the details thereof ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री धर्मवीर यादव) : हां, श्रीमान् जी। वर्ष 1996-97 के दौरान राज्य

सरकार द्वारा हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 1,2,8,10 तथा 22 के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव भेजे गए हैं :-

(क) रख-रखाव तथा मरम्मत	1141.97 लाख रुपये
(ख) राजमार्गों को मजबूत करने/ऊपर ऊठाने/ चौड़ा करने/किनारा पक्का करने/सुरक्षात्मक उपाय/जंक्सन सुधारों आदि के लिए प्रस्ताव।	1093.77 लाख रुपये
(ग) राष्ट्रीय राज मार्ग क्रमांक 1 को किलोमीटर 50 से किलोमीटर 74.80 तथा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 2 किलोमीटर 37.30 से किलोमीटर 93.83 तक (जिसमें दिनांक 31-3-96 तक खर्च की गई 5943.77 लाख रुपये की राशि शामिल नहीं है) मजबूत करने/चौड़ा करने/ऊपर उठाने के लिए संशोधित प्रस्ताव।	7813.63 लाख रुपये
(घ) राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 1 को किलोमीटर 74.80 से किलोमीटर 130.00 तक (जिसमें दिनांक 31-3-96 तक खर्च की गई 2061.588 लाख रुपये की राशि शामिल नहीं है) को मजबूत करने/चौड़ा करने/ऊपर उठाने हेतू संशोधित प्रस्ताव।	9169.94 लाख रुपये

श्री कृष्ण लाल : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नैशनल हाईवेज नं0 1,2,8,10 और 22 हरियाणा प्रदेश में कहां से शुरू हो कर कहां कहां तक जाते हैं और कहां कहां से गुजरते हैं ? इसके साथ-साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार ने भारत सरकार को क्या कोई ऐसा प्रस्ताव भेजा है जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों के सौन्दर्यकरण के लिए जिक्र हो अगर ऐसा प्रस्ताव भेजा है तो उसका अलग से ब्यौरा दें।

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय, एन०एच० नम्बर 1 दिल्ली से अम्बाला, एन०एच० 2 दिल्ली से मथुरा, एन०एच० 8 दिल्ली से जयपुर, एन०एच० 10 दिल्ली से डबवाली और एन०एच० 22 अम्बाला से कालका। इसके अलावा माननीय सदस्य ने प्रस्ताव के बारे में पूछा है। हमने मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस एंड ट्रांस्पोर्ट को जो प्रस्ताव भेजा है उसमें इन राज मार्गों की मैंटीनैंस और रिपेयर्ज के लिए इनकी स्ट्रैन्थनिंग/रिपेयर्ज/वाइडनिंग/हार्ड शोलडरिंग सेफ्टी मइयर्ज और जंकशन इम्प्रूवमैंट आदि सम्मलित हैं।

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने भारत सरकार को जो प्रस्ताव भेजा है उस प्रस्ताव में जिन-जिन कामों पर जितनी राशि खर्च करनी दर्शायी गई है उसमें से कितनी राशि सैंक्शन हुई है, पिछले साल 1996-97 में हरियाणा सरकार को इन कामों के लिए कितनी राशि उपलब्ध हुई और वह कहां-कहां पर खर्च हुई ?

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंटीनैंस एंड रिपेयर्ज के अन्दर 1141.97 लाख रुपये का प्रस्ताव था उसमें से 752 लाख रुपए सैंक्शन हुए। जो मेन सवाल का उत्तर "ख" है उसके लिए 1093.77 लाख रुपए उसमें से 1027 लाख रुपए सैंक्शन हुए। राष्ट्रीय राज मार्ग क्रमांक 1 को किलोमीटर 50 से किलोमीटर 74.80 तक तथा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 2 किलोमीटर 37.30 से किलोमीटर 93.83 तक (जिसमें दिनांक 31-3-96 तक खर्च की गई 5943.77 लाख रुपए की राशि शामिल नहीं है) मजबूत करने/चौड़ा करने/ऊपर उठाने के लिए खर्च किया है। सवाल के भाग "ग" के

10.00 बजे

अन्दर 11231 लाख रुपये की परोपोजल भेजी जिसमें से 2061.588 लाख रुपये 31-3-1996 तक खर्च किये जा चुके हैं। नेशनल हाईवे नं० 1 पर करनाल से समालखा के बीच में और नैशनल हाईवे नं० 1 जो 50 से 74 किलोमीटर तक है वह मुरथल से समालखा के बीच में है इस पर पैसा खर्च किया गया। इसी प्रकार से नेशनल हाई वे 2 पर जो पैसे खर्च किए गए हैं वे सिकरी (बल्लबगढ़) से यू०पी० बोर्डर तक पैसा खर्च किया गया है।

श्री कृष्ण लाल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने राष्ट्रीय राजमार्गों के सौन्दर्यकरण करने की क्या परोपोजल भेजी उसका कोई जिकर अपने जवाब में नहीं किया है।

श्री धर्मवीर यादव : स्पीकर साहब, सौन्दर्यकरण से हमारा मतलब होता है कि रोडज़ अच्छी बने, जहां रेजिंग करनी हो वहां रेजिंग करें या कहीं चौड़ी करनी है या कहीं कलवर्ट बनानी है और जहां कहीं कारपेटिंग करनी है यह सभी काम इसमें शामिल हैं इसी तरह के काम बराबर किये जा रहे हैं।

श्री कृष्ण लाल : अध्यक्ष महोदय, सवाल के जवाब के "क" से लेकर "ग" तक के भाग में सड़कों को चौड़ा करने, मुरम्मत करने किनारों को पक्का करने आदि का जिकर तो पहले ही है। मेरा कहना यह है कि क्या राष्ट्रीय राजमार्गों के सौन्दर्यकरण करने के लिए जिस प्रकार से पंजाब के अन्दर स्टेचू आदि लगाये गए हैं, प्लांटेशन की गई है या और काम किए गए हैं। क्या सौन्दरीकरण के लिए कोई अलग से परोपोजल भेजी गयी है या नहीं ?

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सौन्दर्यकरण के पीछे बहुत ज्यादा दबाव दे रहे हैं। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि वैसे तो इनको इसके लिए अलग से सवाल पूछना चाहिए था लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जहां पर बैजीटेशन की जरुरत है, वहां बैजीटेशन की जा रही है जहां माईल स्टोन की पेंटिंग करने का काम और साइन बोर्ड लगाने का काम किया जा रहा है। इस तरह से सौन्दर्यकरण किया जा रहा है।

तारांकित प्रश्न संख्या 501

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री कैलाश चन्द्र शर्मा सदन में उपस्थित नहीं थे।)

Cases of Murder/Kidnapping/Robbery etc. Registered in the Gurgaon Constituency.

***496. Shri Dharambir Gauba :** Will the Minister for Home be pleased

to state -

(a) the total number of murder, kidnapping, car snatching and robbery registered in Gurgaon Constituency during the period from 1-6-95 to 30-5-96 and 1-6-96 to 30-5-97; and

(b) the number of cases category-wise as referred to in part (a) above have been traced out togetherwith the recovery of stolen goods have been made ?

गृह मंत्री (श्री मनी राम गोदारा) : सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

सूचना

भाग (क)	1-6-95 से 30-5-96	1-6-96 से 30-5-97
हत्या	25	19
अपहरण	24	23
कार छीनना	-	3
लूट	18	17
भाग (ख) खोज निकाले गए मुकदमें		
हत्या	19	10
अपहरण	21	12
कार छीनना	-	3
लूट	13	14

सम्पत्ति की चोरी/बरामदगी

	1-6-95 से 30-5-96		1-6-96 से 30-5-97	
	चोरी	बरामदगी	चोरी	बरामदगी
कार छीनना	—	----	6,00,000.00	6,00,000.00
लूट	14,45,606.00	8,07,000.00	50,62,220.00	8,03,800.00

श्री धर्मवीर गाबा : स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है उसके हिसाब से लगभग 50 लाख रुपये की चोरी हुई और इसमें से लगभग 8 लाख रुपये की राशि अभी तक रिकवर हुई है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसे स्टैप उठा रही है ताकि आगे से हत्या और चोरी के केस न हो सकें ?

श्री मनी राम गोदारा : गवर्नमैंट का सबसे पहला मकसद यह होता है कि ज्यादा से ज्यादा क्राईम को रोका जाए और अगर क्राईम हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा रिकवरी हो। इस मामले में मैं गाबा साहब को यकीन दिलाना चाहूंगा कि सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी।

श्री धर्मवीर गाबा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानकारी चाहूंगा कि क्राईम को रोकने के लिए इन्होंने क्या कोई प्रभावी स्टैप्स उठाए हैं, क्या कोई नये थाने खोलने के बारे में या पुलिस की स्ट्रैंथ बढ़ाने के लिए अथवा अन्य किन्हीं साधनों से क्राईम को रोकने के लिए सरकार क्या सोच रही है ?

श्री मनी राम गोदारा : अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बताना चाहूंगा कि जो भी मुनासिब कार्यवाही की जा सकती है वह हम करने जा रहे हैं।

श्री धर्मवीर गाबा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसमें मेरे सवाल का जवाब नहीं आया है। आप स्वयं देखिये कि क्या यह जवाब सैटिस्फैक्टरी है ? मैंने स्पैसिफिकली यह जानकारी चाही थी कि क्या पुलिस की स्ट्रैंथ बढ़ाई जा रही है या नये पुलिस स्टेशन और बनाए जाएंगे या और कोई वैकल्पिक उपाय किए जाएंगे, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे मेरे सवाल का स्पैसिफिक जवाब देने की मेहरबानी करें।

श्री मनी राम गोदारा : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना मैंने सदन के पटल पर रखी है उसमें हर क्राईम के लिए पूरी सूचना दी गई है। मैं इन्हें फिर यह बताना चाहूंगा कि क्राईम कम हुए हैं, हर क्राईम में रिकवरी ज्यादा से ज्यादा हो रही है। अध्यक्ष महोदय, इस मामले में मैं आनरेबल मैम्बर को यकीन दिलाना चाहूंगा कि जो भी साधन हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्राईम को रोकने के लिए अथवा क्राईम की बरामदगी के लिए वह साधन हम इस्तेमाल करेंगे। अगर इनके पास इस बारे में कोई सुझाव हों तो वे अपने सुझाव भी बताएं। हम अपनी तरफ से जो कार्यवाही उस बारे हो सकती है वह करेंगे। हर प्रकार के क्राईम को रोकने के लिए हम लगे हुए हैं और हर सम्भव साधन का इस्तेमाल हम कर रहे हैं।

श्री धर्मवीर गाबा : अध्यक्ष महोदय, गुड़गांव एक इण्डस्ट्रियल टाउन है। मैं मंत्री महोदय के नोटिस में लाना चाहूंगा कि वहां पर केवल दो पुलिस स्टेशन हैं। इस बारे में मेरा सुझाव है कि वहां पर और पुलिस स्टेशन खोले जाएं ताकि क्राईम को रोका जा सके।

श्री मनी राम गोदारा : स्पीकर सर, मैं आनरेबल श्री गाबा साहब को पहले भी बता चुका हूं कि क्राइम को रोकने के लिए तथा जो क्राइम हो उनकी बरामदगी के लिए जो भी साधन इस्तेमाल किये जा सकते हैं वे इस्तेमाल किये जाएंगे।

श्री धर्मवीर गाबा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्राईम को रोकने के लिए क्या पुलिस की स्ट्रैंथ बढ़ाने या नये पुलिस स्टेशन खोलने की कोई स्कीम सरकार के विचाराधीन है ?

श्री मनी राम गोदारा : अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री गाबा साहब अपने सवाल को पढ़ कर देखें उसमें कहीं पर भी स्ट्रैंथ बढ़ाने या नये पुलिस स्टेशन खोलने की बात नहीं पूछी गई है, अगर यह जानकारी इनको चाहिए तो ये अलग से सवाल पूछ लें मैं जानकारी प्राप्त करके इनको दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : गाबा साहब, आप वर्ष 1995-96 और 1996-97 के फिग्गर्ज देख लें कि क्राईम की संख्या घटी है कि नहीं।

श्री धर्मवीर गाबा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानकारी चाहूंगा कि जो सूचना इन्होंने रखी है क्या वह सही है ? क्या कोई ऐसे केसिज़ भी इनकी जानकारी में हैं जो रजिस्टर नहीं हुए हैं ?

श्री अध्यक्ष : गाबा साहब, आप स्वयं मंत्री रहे हैं इसलिए आपको पता है कि जो सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है वह फैक्ट्स पर बेसड होती है। (विघ्न) गाबा साहब, आप अपनी सीट पर बैठें।

श्री मनी राम गोदारा : अध्यक्ष महोदय, हाउस के अन्दर जो सूचना रखी जाती है वह सही और ठीक रखी जाती है और जो बात कही जाती है वह भी सही कही जाती है, यह इनकी अपनी सोच है कि उसको सही माने या नहीं मानें।

Leasing out of Panchayats Land

***507. Shri Ram Pal Majra :** Will the Minister for Development and Panchayat be pleased to state whether the Panchayat land of Patti Afgan, Patti Chaudhary and Patti Kesth-Seth Villages of Kaithal District was leased out during the year 1995-96, 1996-97 and 1997-98; if so, the total amount realised therefrom ?

विकास मंत्री (श्री कंवल सिंह) : ग्राम पंचायत पट्टी अफगान, पट्टी चौधरी औप पट्टी कायस्थ-सेठ जिला कैथल की पंचायत भूमि वर्ष 1995-96 के लिए 14,51,550/- रु० में पट्टे पर छोड़ी गई थी। स्थानीय निकाय विभाग की अधिसूचना दिनांक 19-3-96 द्वारा इन पंचायतों का क्षेत्र नगर परिषद कैथल में शामिल किया गया। तथापि पट्टी अफगान का अधिकतर क्षेत्र स्थानीय निकाय विभाग की अधिसूचना दिनांक 31-12-97 द्वारा कैथल की नगर परिषद की सीमा से बाहर कर दिया गया है।

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहूंगा कि जो जमीन 1995-96 के लिए पट्टे पर छोड़ी गई है क्या उसकी बोली नहीं हुई ? म्यूनिसिपल कमेटी तथा ग्राम पंचायतों की जो जमीन पट्टे पर छोड़ी गई है उसकी बोली होनी चाहिए थी। जो बोली नहीं हुई है क्या यह पार्टी के 4-5 असरदार कार्यकर्ताओं के दबाव की वजह से नहीं हुई अथवा एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स रही है ?

स्थानीय शासन मंत्री (डॉ० कमला वर्मा) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न स्थानीय निकाय विभाग से जुड़ा हुआ है इसलिये मैं इसका जवाब दे रही हूं। मैं इनको यह बताना चाहूंगी कि हमने इस बारे में केस ए०डी०सी० को भेजा हुआ है और इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ ऐक्शन लिया जाएगा।

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों ने 1996-97 में उस जमीन पर बुआई की थी क्या उनसे पट्टा लेने की कार्यवाही की जाएगी।

डॉ० कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने इनको यह बताया है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ ऐक्शन लिया जाएगा और वसूली भी की जायेगी ।

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, ए०डी०सी० साहब ने इन्क्वायरी रिपोर्ट ग्रीवैंसिज़ कमेटी की मीटिंग में दी थी और अब तक वह नहीं आई है। उस बारे में कुछ नहीं किया है। आज तक कोई कागजात नहीं बना है। यह म्यूनिस्पल कमेटी में या पंचायत में फाल करती है, आप इस बारे में भी बताएं।

डॉ० कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं होगा। अब यह हिस्सा कमेटी में आया है और कमेटी ने इसको निलामी की और इस वर्ष 16.61 लाख रुपये वसूल किए गए हैं। मैं इनको यह बताना चाहूंगी कि जैसे ही ए०डी०सी० महोदय की रिपोर्ट आएगी और उसमें जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और पूरा पैसा वसूल किया जाएगा ।

Allotment of Land to Kumhar Caste

***509. Shri Banta Ram Balmiki :** Will the Minister for Development and Panchayat be pleased to state –

(a) the districtwise total number of applications received todate from the persons belonging to Kumhar Caste for the allotment of land for digging clay to make pottery; and

(b) the number of applications out of those as referred to in part (a) above, to whom the land has been allotted ?

विकास मंत्री (श्री कंवल सिंह) : "क" तथा "ख" बारे वांछित सूचना अनुबन्ध "1" में दी गई है।

अनुबन्ध "1"

		(ए)	(बी)
क्र० सं०	जिले का नाम	कुम्हार जाति के व्यक्तियों से आज तक की तिथि तक प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या	भाग "ए" में से जिनमें भूमि आरक्षित कर दी गई है के आवेदनों की संख्या
1	2	3	4
1.	सोनीपत	202	202
2.	हिसार	20	14
3.	भिवानी	2	2
4.	कुरुक्षेत्र	25	25
5.	करनाल	22	22
6.	महेन्द्रगढ़	शून्य	शून्य
7.	फतेहाबाद	3	3
8.	सिरसा	शून्य	शून्य
9.	कैथल	8	4
10.	पानीपत	16	16
11.	यमुनानगर	शून्य	शून्य

1	2	3	4
12.	रिवाड़ी	शून्य	शून्य
13.	अम्बाला	57	शून्य
14.	गुड़गांवा	1	1
15.	रोहतक	103	90
16.	जीन्द	4	4
17.	झज्जर	शून्य	शून्य
18.	फरीदाबाद	5	4
19.	पंचकूला	21	शून्य
	जोड़	489	387

श्री बन्ता राम बाल्मीकि : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय के जवाब से सन्तुष्ट नही हूं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन्होंने कुम्हार जाति को बर्तन बनाने के लिए मिट्टी खोदने हेतु जमुनानगर में जमीन क्यों नहीं दी ? यहां के कुम्हार किस तरह से अपने बच्चों का पेट पालेंगे। अध्यक्ष महोदय, किसी गांव में पंचायतों के पास जो जमीन है उस जमीन की मिट्टी से बर्तन नहीं बनते और अगर वहीं पर किसी जमींदार के पास चिकनी मिट्टी वाली जमीन है तो क्या सरकार के पास ऐसा विचार है कि वे जमींदार की जमीन लेकर उनकी जमीन से बदल दें ?

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल) : अध्यक्ष महोदय, इनकी बात ठीक है कि कुम्हारों को स्टेट में कई जगहों पर तकलीफ आ रही है और उनको मिट्टी के बर्तन बनाने लायक मिट्टी नहीं मिल रही है। हम इसके लिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को हिदायत करेंगे कि जहां पर भी पोसिबल हो उनको बर्तन बनाने के लिए मिट्टी निकालने की जमीन मुहैया करवाने की कोशिश करें।

Repair of Roads

***518. Shri Ramesh Kumar :** Will the Minister for PWD (B&R) be pleased to state the time by which the following damaged roads of Baroda constituency will be repaired :-

(i) Mehmudpur to Chhatehra;
(ii) Dhurana to Badhothi;
(iii) Butana to Ranakheri;
(iv) Kohla to Nizampur;
(v) Kohla to Banwasa;
(vi) Madina to Mirjapur Kheri; and
(vii) Dhanana to Kathura ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री धर्मवीर यादव) : लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें शाखा) से संबंधित क्रमांक (i) से (iv) तथा (vi) पर दर्शायी गई सड़कों की मरम्मत जून,1998 के अन्त तक कर लिये जाने की संभावना है। क्रमांक (v) पर वर्णित सड़क, जो कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की सड़क है, की मरम्मत वर्ष 1996-97 के दौरान की गई थी तथा इसकी आगामी वित्त वर्ष के लिए वार्षिक मरम्मत जून, 1998 के अन्त तक कर ली जाएगी।

क्रम संख्या (vii) पर वर्णित सड़क के एक बड़े भाग की विशेष मरम्मत हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा वर्ष 1996-97 के दौरान कर ली गई थी तथा शेष भाग को विशेष मरम्मत के अन्तर्गत वर्ष 1998-99 के दौरान शामिल किया जाएगा। तथापि, इस सड़क को मार्च, 1998 के अन्त तक वार्षिक मरम्मत कार्यक्रम के अन्तर्गत भी शामिल कर लिया जाएगा।

श्री रमेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी है उसमें दर्शाया गया है कि सरकार ने वर्ष 1996-97 में जिन सड़कों की मरम्मत की थी या जो बकाया सड़कें हैं उनकी जून, 1998 तक मरम्मत कर दी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, पिछले सैशन में भी मैंने महमूदपुर से छतेरड़ा, धुराना से बाढ़ोठी, बुदाना से राणाखेड़ी, कोहला से निजामपुर, कोहला से बनवासा, मदीना से मिर्जापुर खेड़ी और धनाना से कंधूरा की सड़कों के बारे में मंत्री जी से पूछा था तो उन्होंने उस समय कहा था कि हम यह सड़कें बनवाएंगे और इनकी 1997-98 तक रिपेयर की जाएगी लेकिन आज तक भी मेरे हल्के में इन सड़कों की मरम्मत नहीं की गयी है। मंत्री जी कृपया बतलाएं कि जो रिपोर्ट इन्होंने सड़कों के बारे में दर्शायी है उसको ये कब तक मेरे हल्के में पूरा कर देंगे ?

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय, पी०डब्ल्यू०डी०और मार्कीटिंग बोर्ड सड़कों की मरम्मत साफ मौसम के दौरान ही करते हैं जैसा कि विदित है कि पिछले वर्ष के दौरान भी काफी बरसातें होती रही हैं क्योंकि मौसम इस बार जल्दी आया और बहुत देर से गया। दिसम्बर के अंदर भी बरसातें होती रहीं यानी लगभग सावन जैसा महीना रहा इसलिए सर, ऐसे मौसम में सड़कों की मरम्मत नहीं की जा सकती परन्तु यह विभाग और सरकार इस बात के लिए वचनबद्ध हैं कि मौसम के ठीक होते ही इन सड़कों की मरम्मत कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, सड़कों की मरम्मत करने से पहले जो प्रशासनिक कार्यवाही करनी होती है, वह हम कर चुके हैं ऐस्टीमेट्स बन चुके हैं ऐस्टीमेट्स पास हो चुके हैं और इन पर कार्यवाही चल रही है।

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा अपने लायक मंत्री जी से विषय से अलग हटकर थोड़ी सी जानकारी चाहूंगा और मुझे उम्मीद है कि वह इस बारे में तैयार भी होंगे। अध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश में जो लिंक रोड्ज हैं या मेन सड़कें हैं जो एक शहर से दूसरे शहर में जाती हैं। कुछ ऐसे गांव हैं जहां उनकी रेजिंग की जा रही है। 3-4-5 या 6 फुट तक रेजिंग हो गई है। आम आदमी जिन्होंने मकान बनाए हैं वे इससे बहुत प्रभावित हुए हैं। जो सुविधा सरकार देना चाहती है उसकी एवज में जिन्होंने मकान बनाए और वे प्रभावित हुए उससे ज्यादा घाटा हो गया इसलिए मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि सड़क को ऊंचा उठाया जाना कोई समस्या का समाधान नहीं है। पानी की निकासी पर विशेष ध्यान होना चाहिए। हमारे इलाके में जो इसके परिणाम आने चाहिए थे जो सोच कर रेजिंग की थी उससे कोई लाभ नहीं हुआ है उल्टे मकान 5-6 फुट नीचे चले गए उससे वहां लोगों का रहना दूभर हो गया है इसलिए आप इस पर दोबारा विचार कर लें। अभी इसके लिए समय है। इस पर पैसा खर्च हो रहा है। यह पैसा प्रदेश का है न आपका है और न मेरा है। आप पानी की निकासी के लिए कोई अलग से विंग बना लें और उस विंग द्वारा जो रिपोर्ट आए उस पर विचार कर लें।

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय, किसी भी गांव में जहां सड़क टूटी हुई है उसकी मरम्मत की जाती है और उसी हिसाब से एक्शन लिया जाता है। उसकी रेजिंग करनी है या उसको कंक्रीट से करना है जिस हिसाब से उचित होता है उसी हिसाब से किया जाता है। इस प्रकार जो कार्यवाही उचित होती है वह कर रहे हैं।

Providing of Domestic Water Connection

***526. Shri Ram Phal Kundu :** Will the Minister for Public Health be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Governmen to provide domestic water connections in the villages in District Jind ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री जगन नाथ) : नहीं, श्रीमान जी।

श्री राम फल कुण्डू : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या हरियाणा प्रदेश में कोई ऐसा गांव है जहां पीने के पानी के कनैक्शन दिए गए हैं। यदि हां, तो किस नार्म के तहत दिए गए हैं ?

श्री जगन नाथ : अध्यक्ष महोदय, आठ जिले ऐसे हैं सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, रोहतक, झज्जर, महेन्द्रगढ़, रिवाड़ी इन जिलों में जिस गांव में 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन पानी की आपूर्ति है वहां हाउस कनैक्शन दे रहे हैं लेकिन जहां 70 लीटर से कम है जैसे 40 या 50 लीटर तक है, वहां हाउस कनैक्शन नहीं दे रहे हैं। यदि कुछ कनैक्शन ऐसे दिए भी जाते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ऐप्रूवल से दिए जाते हैं। पिछली सरकार ने कोई आर्डर किया था कि मंत्री ही खुद हाउस कनैक्शन दे दे चाहे 40 लीटर उपलब्धता ही हो लेकिन वह कुछ जंचा नहीं। इससे दूसरे लोगों को असुविधा रहती थी। जींद जिले के 18 गांवों में ऐसे कनैक्शन दिए गए थे लेकिन इस समय ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

श्री राम फल कुण्डू : जो आपने घरेलू कनैक्शन दिए हैं क्या उसमें जनसंख्या का आधार रखा है ?

श्री जगन नाथ : नहीं, जनसंख्या का आधार नहीं है। पानी की मात्रा होनी चाहिए। जिन गांवों में पानी की मात्रा कम है वहां घरेलू कनैक्शन देने से बाकी सारे का सारा गांव ऐसे ही रह जाएगा, उनको पानी नहीं मिलेगा। किसी रेयर केस में मुख्यमंत्री जी की ऐप्रूवल से कनैक्शन दिया जा सकता है अदर-वाइज नहीं।

श्री दिलूराम : स्पीकर सर, यह जो वाटर सप्लाई हर गांव तथा हर डेरे में देने की बात कही जा रही है उसके बारे में एक बड़ा भारी नुक्स है कि जो प्लास्टिक के पाइप दिए जाते हैं वे जल्दी ही खराब हो जाते हैं तथा किसानों की फसलों को खराब करते हैं। यह बात पता नहीं मंत्री जी के नोटिस में है या नहीं। जब संबंधित अधिकारियों से बात की जाती है तो वे कहते हैं कि हमारे पास तो ऐसे ही पाइप आते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप सवाल पूछिये।

श्री दिलू राम : स्पीकर सर, मेरे हल्के में डेरे ज्यादा हैं। वहां पर हर वर्ष किसानों की फसल खराब हो जाती है इसका कोई तो समाधान मंत्री जी करें।

श्री जगन नाथ : अगर ऐसी कोई बात है तो हमें लिखकर दे दें हम ठीक करवा देंगे। हम तो सबसे बढ़िया पाईप सप्लाई करवाते हैं और लोगों को बढ़िया पानी पिलाते हैं। आप को भी चुनाव में पानी पिलाऐंगे। (हंसी)

श्री दिलू राम : कम से कम लोगों को तो खराब पानी न पिलाओ।

श्री अध्यक्ष : चौधरी बलवंत सिंह मायना।

श्री बलवंत सिंह : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से जन-स्वास्थ्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन्होंने जो 8 जिलों के गांवों में घर-घर पानी के कनैक्शन देने की बात कही है क्या वे बतायेंगे कि रोहतक जिले के कितने गांवों में घर-घर पानी का कनैक्शन दिया है ?

श्री जगन नाथ : आपको इतना तो पता है कि जहां पानी की कमी है वहां तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से ही पानी का कनैक्शन दे पाते हैं वरना जहां 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का पानी उपलब्ध है वहां पर घर-घर पानी का कनैक्शन हमने दिया है।

श्री बलवन्त सिंह : स्पीकर सर, रोहतक जिले के एक गांव का नाम तो मंत्री जी बतायें।

श्री जगन नाथ : इनके खुद के हल्के सांपला के गांवों में जाकर देखें।

श्री बलवंत सिंह : स्पीकर सर, सांपला के गांवों में आप जाकर देखें सिर्फ गांव की गलियों में तो पानी के कनैक्शन हैं लेकिन घर-घर में कनैक्शन नहीं हैं। आप चाहें तो कमेटी बनाकर जांच करा लें।

श्री जगन नाथ : ये गांव में जाते ही नहीं आप वहां पर जाकर देखें हमने हाउस कनैक्शन दिये हैं।

श्री बलवंत सिंह : गलियों में कनैक्शन दिए हैं यह तो मैं भी मानता हूं लेकिन गांव के अन्दर घरों में कनैक्शन नहीं दिए हैं।

श्री जगन नाथ : गलियों में तो हमने सारे प्रान्त में पानी के कनैक्शन दे रखे हैं।

श्री बलवन्त सिंह : आप कमेटी बना लें, वह पता कर लेगी।

श्री अध्यक्ष : मायना साहब, क्या सांपला आपकी कांस्टीच्यूएंसी में ही है ?

श्री बलवन्त सिंह : स्पीकर सर, आपको इतना भी ज्ञान नहीं कि सांपला मेरी कान्सटीच्यूएंसी में है या नहीं ? आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि पिछले बजट सैशन में यहां दो-अढ़ाई घण्टे तक जिस बात पर हंगामा रहा और सैशन नहीं चल पाया था वह सांपला के कालेज की बात थी।

श्री अध्यक्ष : अब क्वैश्चन आवर समाप्त होता है।

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Dabwali Fire Tragedy

*555. **Shri Mani Ram :** Will the Minister for Local Government be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a monument in the memory of the deceased of the Dabwali tragedy ?

स्थानीय शासन मंत्री (डॉ0 कमला वर्मा) : भू मालिक से त्रासदी स्थल पर स्मारक हेतू दान के रूप में भूमि प्राप्त करने के सरकार द्वारा किये गये प्रयास सफल नहीं हुये। इसलिए स्मारक का निर्माण कार्य अब तक प्रारम्भ करना संभव नहीं हो सका है।

Upgradation of Schools

*463. **Shri Dev Raj Dewan :** Will the Minister for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to up-grade the Government High School Pinana to 10+2 and Government Primary School, Duduwa to Middle School in District Sonipat ?

शिक्षा मंत्री (श्री राम विलास शर्मा) : अभी इन स्कूलों को अपग्रेड करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Post Graduation Regional Institute, Meerpur

*484. **Capt. Ajay Singh :** Will the Minister for Education be pleased to state-

(a) the present stage of the construction work of the Post Graduate Regional Centre, Meerpur in District Rewari; and

(b) the total amount spent on the aforesaid centre during the year 1995-96, 1996-97 and 1997 to date; togetherwith the time by which it is likely to be completed ?

शिक्षा मंत्री (श्री राम विलास शर्मा) : "क" तथा "ख" कथन सदन के पटल पर रख दिया गया है।

कथन

(क) दिनांक 17-11-97 को क्षेत्रीय स्नातकोत्तर केन्द्र, मीरपुर में निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :-

क्षेत्रीय स्नातकोत्तर केन्द्र, मीरपुर में लगभग 1400 मीटर लम्बी सड़क का निर्माण किया जा चुका है। द्विमार्गी के एक मार्ग को पक्का करके मुख्य सड़क पूर्ण की जा चुकी है। दूसरे मार्ग को मिट्टी की भराई तक पूर्ण किया जा चुका है। इसको पक्का करने का कार्य, शिक्षण संकायों व प्रशासकीय खण्ड के निर्माण के पश्चात् आरम्भ किया जायेगा। गांव की सीमा को छूने वाले कुछ भाग को छोड़कर, समस्त 100 एकड़ भूमि के चारों ओर (लगभग) 2636 मीटर लम्बी चार दीवारी का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है।

[श्री राम बिलास शर्मा]

(ख) खर्च की गई राशि इस प्रकार है :-

वर्ष	खर्च की गई राशि (रुपये लाखों में)
1995-96	9.44
1996-97	50.78
1997-98 (17-11-97 तक)	2.25

राज्य सरकार के परामर्श पर विश्वविद्यालय ने इस प्रौजेक्ट को यू०जी०सी० से अनुमोदित करवाने हेतु समिति गठित कर दी है। इससे विश्वविद्यालय को इस प्रौजेक्ट को पूरा करने हेतु यू०जी०सी० से भी वित्तीय सहायता प्राप्त करनी सम्भव होगी। इस सैन्टर का निर्माण कार्य नवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूर्ण होने की आशा है।

Repair of Roads

***491. Shri Krishan Lal :** Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state-

(a) Whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the following roads :-

(i) Kavi to Dharamgarh (Panipat);
(ii) Kiral to Baljattan via Khandra (Panipat);
(iii) Salwan to Kurlan (Karnal);
(iv) Assandh to Dera Gujrakhian;
(v) Assandh to Dera Gamm;
(vi) Dupedi to Phapharana; and
(vii) Salwan to Kabulpura Khera; and

(b) if so, the time by which the said roads are likely to be repaired ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री धर्मवीर यादव) :

(क) हां, श्रीमान् जी।

(ख) मार्च, 1998 तक।

Lining of Sewerage of Narnaul

***502. Shri Kailash Chander Sharma :** Will the Minister for Public Health be pleased to state whether it is a fact that lining work of sewerage of Narnaul is lying incomplete, if so, the reasons thereof together with the time by which it is likely to be completed ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री जगन नाथ) : सीवरेज प्रणाली में लाईनिंग नहीं की जाती। नारनौल में सीवरेज के विस्तार का कार्य दो अनुमोदित अनुमानों, जिनकी राशि 85.85 लाख रुपये है के अन्तर्गत

किया जा रहा है। कार्य की प्रगति धन राशि की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

***497. Shri Dharambir Gauba :** Will the Minister for Industries be pleased to state –

(a) the total number of industries have been set up in Large, Medium and Small Sectors in the State particularly in Gurgaon during the period from 1-6-96 to 30-10-97; and

(b) the details of the incentive, if any given to the industries as referred to part (a) above ?

उद्योग मंत्री (श्री शशि पाल मेहता) :

(क) दिनांक 1-6-96 से 30-10-97 तक की अवधि के दौरान स्थापित औद्योगिक इकाइयों की संख्या निम्न प्रकार से है :-

	बड़ी तथा मध्यम	लघु इकाइयां
राज्य भर में	106	7887
गुड़गांव जिला	43	968

(ख) पात्र औद्योगिक इकाइयों को समय-समय पर निर्धारित राज्य की औद्योगिक नीति के अनुसार प्रोत्साहन दिये जाते हैं जैसे बिक्री कर छूट/स्थगन, पूंजी निवेश अनुदान, जनरेटिंग सैट अनुदान, चुंगी कर से छूट, बिजली शुल्क में छूट तथा मूल्य अधिमान।

Scarcity of Drinking Water

***517. Shri Randeep Singh Surjewala :** Will the Minister for Public Health be pleased to state-

(a) whether it is a fact that there is acute scarcity of drinking water in the following colonies of Narwana City :–

(i) Prem Nagar, near old bus stand, Narwana;

(ii) Indira Colony, Tohana road, Narwana;

(iii) Shiv Colony, Opp. Indira Colony, Tohana road, Narwana;

(iv) Dara Mohalla, Narwana;

(v) Patel Nagar, Narwana;

(vi) Mor Patti, Narwana;

(vii) Old Dhani, Narwana; and

(b) if so, the reasons thereof together with the steps taken or proposed to be taken to meet out the said scarcity of drinking water in the above said colonies ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री जगन्नाथ) :

(क) और (ख) गर्मी के मौसम में पीने के पानी की कुछ कमी है जिसे दूर करने के लिये उचित पग उठाये जा रहे हैं।

Metalled Road

***513. Shri Banta Ram Balmiki :** Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a matalled road from village Ghilour to Hartan Majri via Hira Chhapar in district Yamuna Nagar ?

लोक निर्माण मन्त्री (श्री धर्मवीर यादव) : नहीं, श्रीमान जी।

Drain out the Sewerage Water of New Grain Market, Kaithal

***560. Shri Ram Pal Majra :** Will the Minister for Public health be pleased to state -

(a) whether it is a fact that the sewerage water of New Grain Market, Kaithal accumulates on the Chandana road; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to drainout the said water into Amin-drain ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री जगन्नाथ) :

(क) भारी वर्षा के समय कुछ सीवर तथा वर्षा का गन्दा पानी नाले से निकल कर चन्दाना सड़क के एक किलोमीटर भाग में फैल जाता है।

(ख) सतलेज कैरियर को मजबूत करने की योजना विचाराधीन है।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Octroi Duty

33. Capt. Ajay Singh Yadav : Will the Minister for Local Government be pleased to state--

(a) whether the State Government has increased octroi duty during the current financial year; if so, the details thereof; and

(b) whether criteria for collecting octroi duty has been changed; if so, the details thereof; together with the amount of revenue to be col-

lected during the period as referred to in part (a) above on account of the change in criteria ?

स्थानीय शासन मंत्री (डॉ० कमला वर्मा) :

(क) जी नहीं,

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Raid conducted on Sugar Mill, Shahbad

34. Shri Krishan Lal : Will the Minister for Cooperation be pleased to state -

(a) whether any inspection/checking/raid has been conducted in Sugar Mill, Shahbad during the year 1997-98; if so, the details thereof;

(b) whether the sugar of said Mill has been exported during the period referred to in part (a) above: if so, the total quantity and the rate thereof;

(c) whether the Government is aware of the fact that privately owned Sugar Mills in the State has also exported the Sugar if so, the rate of the sugar so exported;

(d) whether the rate of sugar exported as referred to in part above is higher than that of sugar exported by Cooperative Sugar Mills; if so, the reasons thereof;

(e) whether the boiler parts of the said Mills has been purchased during the year 1996-97; if so, whether the quotation has been procured for the purchase of said parts, if not, the reasons thereof; and

(f) whether any officer/official has been sent to purchase the afore-said part on the spot, if so; the total expenditure incurred thereof ?

सहकारिता मंत्री (श्री नरबीर सिंह) :

(क) जी हां ! शाहबाद सहकारी चीनी मिल में वर्ष 1997-98 में भारतीय शर्करा मानक से निम्न कोटी की चीनी मिल के भण्डार का सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, हरियाणा व तकनीकी सलाहकार (अभियन्त्रण) चीनी मिल प्रसंघ द्वारा निरीक्षण किया गया था तथा कुछ बोरियां कम भार की पाई गई।

(ख) मिल ने कुल 1.25 लाख क्विंटल चीनी अटारी बार्डर पर 1205 रुपए प्रति क्विंटल से 1250 रुपए प्रति क्विंटल तक की दर से निर्यात किया।

(ग) यह रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि निजी क्षेत्र की भादसों जिला करनाल स्थित चीनी मिल ने पाकिस्तान को अमेरिकन 363 डालर प्रति मीट्रिक टन पर अटारी बार्डर पर निर्यात किया है।

(ग) यह मामला राज्य चौकसी ब्यूरो द्वारा जांच किया जा रहा है।

(ब) बायलर के पुर्जे वर्ष 1996-97 में खरीदे गए। कथित पुर्जों की खरीद के लिए कोई निविदा प्राप्त नहीं की गई। जबकि मैसर्ज त्रिवेणी इन्जीनियरिंग वर्क्स ने बायलर मैसर्ज वालचन्द नगर इन्डस्ट्रीज लि० जो मूल निर्माता हैं के माध्यम से सप्लाई किए, ये पुर्जे चीनी मिल प्रबंध हरियाणा के तकनीकी सलाहकार (अभियन्त्रण) के सुझाव पर मै० वालचन्द नगर इण्डस्ट्रीज लि० से 9.50 लाख रुपए में खरीदे गए।

(च) मिल के मुख्य इंजीनियर को उपरोक्त पार्टस खरीदने के लिए भेजा गया तथा 13300 रुपए उसके यात्रा भत्ता पर खर्च आया। मुख्य इंजीनियर ने अपना यात्रा भत्ता बिल भुगतान हेतु मिल में प्रस्तुत कर दिया है।

Outstanding Amount of Electricity Charges

35. Shri Ram Pal Majra
Shri Virender Pal Ahalawat } : Will the Chief Minister be pleased to state whether any amount of arrears on account of electricity bills are outstanding against various Government Departments, Boards and Coporations and Industrial Sector as on 31-10-1997, if so, the amounts, names and addresses thereof togetherwith the steps, if any, taken or proposed to be taken to recover the said amount ?

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल) : हां श्रीमान् जी। विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों एवं उद्योगों के बारे में बिजली बिलों से सम्बन्धित नामों, पतों एवं बकाया धन राशि का ब्यौरा पूरे राज्य में स्थित 233 उप-मंडलीय कार्यालयों एवं उप-कार्यालयों में रखा जाता है। इस सम्बन्ध में सारे राज्य से सूचना का इकट्ठा करना तथा मिलान करना एक लम्बा कार्य है जो प्रयत्न करके मंगाने के बाद भी समय पर सुलभ होना मुश्किल है। अक्तूबर 1997 तक की समाप्ति तक कुल बकाया धन राशि का ब्यौरा निम्न प्रकार उद्धृत किया जाता है :-

1. सरकारी/अर्ध सरकारी विभाग

विभाग का नाम	कनैक्शनों के नाम	धन राशि (लाखों में)
लघु सिंचाई एवं ट्यूबवैल निगम	1259	1002.27
हरियाणा सिंचाई विभाग	895	4802.64
म्यूनिसिपल निगम	419	568.57
पंचायत	993	150.81
सार्वजनिक स्वास्थ्य	3938	2221.67
अन्य	904	1281.62
	8408	10027.58
2. औद्योगिक उपभोक्ता	27892	9899.62

बकाया धन राशि को वसूल करने के लिए उठाए गए कदम

बिलों की बकाया धन राशि को वसूल करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं :-

(क) ऐसे दोषी सरकारी उपभोक्ता जो अनिवार्य सेवा प्रदान नहीं कर रहे हैं, उनके कनैक्शन तेजी से काटना।

(ख) दोषी औद्योगिक उपभोक्ताओं के कनैक्शन तत्काल काटना।

(ग) अनेक स्तरों पर जिसमें बोर्ड मुख्यालय भी सम्मिलित हैं, राजस्व अनुमान एवं वसूली पर एक गहन निगरानी रखना।

(घ) जहां कहीं भी मुकदमेबाजी चल रही हो, वहां कोर्ट के बाहर उनके लिए दोषी औद्योगिक उपभोक्ताओं के साथ विचार-विमर्श करना।

Replacement of Iron Electrical Poles

36. Sh. Ram Phal Kundu : Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the names of the villages where iron electrical poles have been installed in Safidon constituency; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to replace the iron poles with cement poles in the villages referred to in part (a) above ?

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल) :

(क) ह०रा०वि० बोर्ड द्वारा उक्त सूचना परिचालन मण्डलानुसार रखी जाती है, चुनाव क्षेत्र के अनुसार नहीं रखी जाती। माँगी गई सूचना इकट्ठी की जा रही है जिसे एक महीने के अन्दर-अन्दर प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

(ख) गांवों में लगाए गए सभी स्टील के खम्बों को सीमेन्ट के खम्बों द्वारा बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी ऐसे सभी पुराने स्टील के खम्बे जो काफी पुराने या जर्जर हो गए हैं उन्हें सामान्य अनुरक्षण (रख-रखाव) के दौरान सीमेन्ट के खम्बों द्वारा बदला जा रहा है।

स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैंने काम-रोको प्रस्ताव आपके सैक्रेटैरिएट को दिया है। उसका फैसला कब तक हो जाएगा। वह एक दर्जन किसानों की पुलिस फायरिंग में की गई हत्या के बारे में है।

Mr. Speaker : That has been rejected.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, *******

Mr. Speaker : Nothing to be recorded. Surjewala Ji, please take your seat.

Shri Randeep Singh Surjewala : Mr. Speaker, I want to say *****

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

Mr. Speaker : Mr. Surjewala, I warn you. Please take your seat. (Interruptions)

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, जीरो आवर में अपनी बात कहने का अधिकार तो सभी को है। (शोर)

श्रीमती करतार देवी : अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण मामला है। 12 किसानों की मृत्यु हुई है और इलाके में चारों तरफ हा-हा कार मची हुई है जिसके लिए हम एक काम-रोको प्रस्ताव सदन में लाए हैं, इस प्रस्ताव को आपके द्वारा रिजैक्ट नहीं किया जाना चाहिए था। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप इस पर पुनर्विचार करें और हाऊस में हमें अपनी बात कहने का अवसर प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष : मैं श्री सुर्जेवाला और बहिन करतार देवी को बताना चाहता हूं कि आज माननीय वित्त मंत्री जी ने अपनी स्पीच देनी है और आज के दिन नियमानुसार जीरो आवर नहीं होता है। इसलिए आज यह एजैंडा टेक-अप नहीं किया जाएगा।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, यह मामला जीरो आवर का नहीं है (शोर) यह तो उन एक दर्जन किसानों की समस्याओं से जुड़ा हुआ मामला है। (शोर)

श्री सतपाल सांगवान : अध्यक्ष महोदय, इनको क्या मालूम है कि किसानों की समस्याएं क्या होती हैं। ये तो यहां पर क्रीम लगाकर आ जाते हैं। (शोर)

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है कि कम से कम सदन को तो इस बात की जानकारी दी जानी चाहिए थी कि आज वित्त मंत्री महोदय की स्पीच होगी। (शोर)

वाक-आउट

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, यह एक अहम मामला है जिसको आप गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं इसलिए मैं एज ए प्रोटैस्ट सदन से वाक-आउट करता हूं।

(At this stage Shri Randeep Singh Surjewala staged a walkout.)

नियम 121 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move the motion under Rule 121.

Minister of State for Parliamentary Affairs (Shri Attar Singh Saini) : Sir, I beg to move –

That the provisions of Rule 228, 230, 230-B and 260-A of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly in-so-far as they relate to the constitution of the-

(i) Committee on Public Accounts;

(ii) Committee on Estimates;

(iii) Committee on Public Undertakings; and

(iv) Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes.

for the year 1998-99 be suspended.

Sir, I also beg to move-

That this house authorises the Speaker, Haryana Vidhan Sabha, to nominate the Member of the aforesaid Committees for the year 1998-99, keeping in view the proportionate strength of various parties/groups in the House.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the provisions of Rule 228,230, 230-B and 260-A of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly in-so-far as they relate to the constitution of the -

(i) Committee on Public Accounts;

(ii) Committee on Estimates;

(iii) Committee on Public Undertakings; and

(iv) Committee on the Welfare of Scheduled Castes Scheduled Tribes and Backward Classes.

for the year 1998-99 be suspended.

and also

That this House authorises the Speaker, Haryana Vidhan Sabha, to nominate the Members of the aforesaid Committees for the year 1998-99, keeping in view the proportionate strength of various parties/groups in the House.

स्थगन प्रस्ताव की सूचना (पुनरारम्भ)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं प्वाएंट ऑफ आर्डर पर बोलना चाहता हूं। एक काम रोको प्रस्ताव आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया। यह बात आपके अधिकार में है कि आप चाहे इसको रिजैक्ट करें या स्वीकृत करें। अध्यक्ष महोदय, हाऊस के ब्यूज़ तो लोगों तक पहुंचने चाहिएं। यह एक अहम् मुद्दा है जिस पर चर्चा करवाई जानी चाहिए। अगर ऐसी बात थी कि आज वित्त मंत्री महोदय ने अपनी स्पीच देनी है तो इस बारे में सदन को पहले ही सूचित कर दिया जाना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष : क्या आपके पास आज का एजैंडा नहीं पहुंचा है ?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, *******

श्री अध्यक्ष : मेरी परमीशन के बगैर जो कुछ बोला जा रहा है वह रिकार्ड न किया जाए। (शोर)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अगर आपने जनतांत्रिक तरीके से हमारी मुनासिब बात नहीं सुननी तो बेहतर है कि हम सदन में न बैठें। काम रोको प्रस्ताव एक अहम् मुद्दा है। सारे हरियाणा में कोहराम मचा हुआ है। लोगों के घरों में तवा भी नहीं चढ़ा है। (शोर)

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

Mr. Speaker : Please don't try to interrupt the proceedings. Please listen to me. दूसरी सिटिंग में गवर्नर एड्रैस पर बहस होगी तो बोल लेना तब आपको कौन रोकने वाला है? Now you cannot speak. Please take your seat. (Interruptions).

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, काम रोको प्रस्ताव एक अहम मुद्दा है उस पर चर्चा करवाई जाए। जब आप विपक्ष में थे और कादमा कांण्ड पर चर्चा चल रही थी उस समय आपकी क्या स्थिति थी और अब आप इतने विपरीत क्यों दिखाई दे रहे हैं? आप बदले हुए नजर आ रहे हैं।

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं ओनरेबल मैम्बर को बता दूं कि इनको याद होगा कि पिछले राज में जिस दिन बजट पेश होना था उस दिन मुझे पर्सनल एक्सप्लेनेशन देनी थी लेकिन मुझे समय नहीं दिया गया। आपके प्रैडीसैसर ने कहा कि जिस दिन बजट होता है उस दिन पर्सनल एक्सप्लेनेशन नहीं दी जाती इसलिए आप कल देना और कल फिर कहा कि आप कल दे देना। इस तरह तीन दिन बीत गए और वे हाउस एडजर्न करके चले गये। आज तक मुझे पर्सनल एक्सप्लेनेशन देने का मौका नहीं मिला। यदि उस वक्त यह कानून था तो क्या आज कानून बदल गये हैं।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण -

श्री ओम प्रकाश चौटाला द्वारा

श्री ओम प्रकाश चौटाला : लीडर ऑफ दि हाउस ने कहा कि अब तक मेरी बात का स्पष्टीकरण नहीं लिया गया। ये सारे स्पष्टीकरण 16 फरवरी तक आ जाएंगे। आपको ये जवाब लोगों के बीच जाकर देने पड़ेंगे तो पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं।

श्री बंसी लाल : 16 फरवरी दूर नहीं है आपको बता देंगे कि आप कहां खड़े हुए हैं।

ओम प्रकाश चौटाला : आपको तब पता चलेगा जब आप लोगों के बीच जाएंगे। जब ये किसी जनसभा में बोलने के लिए खड़े होते हैं तो जनता उठकर चली जाती है। इनकी यह स्थिति है।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, ओम प्रकाश चौटाला की गल्त बात कहने की आदत है। जब ये दिखाई देते हैं तो लोगों को समझ आता है कि ये कहीं इस सीट पर न आ बैठें इसलिए लोग भाग जाते हैं। लोग खड़े इसलिए नहीं रहते कि यह मनहूस आदमी दोबारा न आ जाए।

स्थगन प्रस्ताव की सूचना (पुनरारम्भ)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : स्पीकर साहब, आप मेरी बात तो सुनें (शोर)

श्री अध्यक्ष : आप बैठें। आपको बोलने का पूरा मौका मिलेगा चाहे आप रात के 12.00 बजे तक हाउस को चलाएं। (शोर)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय आप मेरी सबमिशन तो सुन लें। (शोर)

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब कृपया आप बैठ जाएं।

श्री धीर पाल सिंह : स्पीकर साहब, मेरी एक सबमिशन है। (शोर)

श्री अध्यक्ष : धीर पाल जी, मोशन मूव हो चुका है आप कृपया बैठें। (शोर)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आपकी बात ठीक है कि आप हमें रात के 12.00

बजे तक बोलने का मौका देंगे लेकिन मुझे यह दिखाई दे रहा है कि जैसे रेडियों में एक धुन बज रही थी कि सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे। वह तो हो जाएगा लेकिन वह एक अहम् मुद्दा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सतपाल सांगवान : स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। (शोर)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इनको लोग गांव में नहीं घुसने देते । (शोर)

श्री सतपाल सांगवान : स्पीकर साहब, इनको लोग गांव में नहीं घुसने दे रहे हैं। ये मेरे हल्के में 35 गाड़ियां लेकर गए थे और उन गाड़ियों में जितने आदमी बैठे थे उनके पास दो-दो पिस्तौल थे। इनको लोग गांव में नहीं घुसने दे रहे हैं।

श्री धीर पाल सिंह : स्पीकर साहब, मैं आपसे बोलने के लिए समय मांग रहा हूं लेकिन मुझे समय नहीं मिल रहा है। हम चेयर का आदर करते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री धीर पाल सिंह : स्पीकर साहब, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि हाउस में एक काम रोको प्रस्ताव आया उस पर आपने जो फैसला किया उस फैसले पर आप पुनर्विचार करें।

श्री अध्यक्ष : आप उस बारे में न बोलें, यदि आपने कोई और बात कहनी है तो कहें।

श्री धीर पाल सिंह : स्पीकर साहब, मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि आप अपने उस फैसले पर पुनर्विचार करें।

Mr. Speaker : Please do not try to interrupt the proceedings. (Interruptions). Please take your seat. Let me move the motion.

श्री धीर पाल सिंह : स्पीकर साहब, हम यह मानते हैं। मेरी दूसरी बात यह है कि हम चेयर का हमेशा आदर करते हैं।

श्री अध्यक्ष : इसके लिए आपका धन्यवाद।

श्री धीर पाल सिंह : स्पीकर साहब, ट्रेजरी बैंच के एक माननीय सदस्य ने बगैर आपकी इजाजत लिए अपनी बात कह दी। इसके अलावा सदन के एक नेता ने एक बात यह कही कि इनका (हमारा) कांग्रेस पार्टी के साथ सहयोग है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी का कांग्रेस पार्टी के साथ कोई लेन-देन नहीं है। हम किसी के हमदर्द हैं तो गरीब और किसानों के हमदर्द हैं। हमें किसानों की समस्याओं के लिए और गरीबों की समस्याओं के लिए जो भी त्याग करना पड़ा, जो भी पीड़ा सहनी पड़ी उस पीड़ा को हम सहन करेंगे। हम अन्तिम समय तक किसानों के लिए संघर्ष करते रहेंगे।

कृषि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल) : अध्यक्ष महोदय, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने और धीर पाल जी ने एक बात कह दी कि मुख्य मंत्री जी जब कोई जलसा करते हैं तो लोग उठ कर चले जाते हैं। यह इन्होंने बहुत गलत बात कही है (शोर) स्पीकर साहब, ये भाई हमारी सरकार की लोकप्रियता से बौखलाए हुए हैं। इन्होंने हमारी जनसभाओं के बारे में पता करना है तो इनको लोगों से पूछना चाहिए। (शोर) ओम प्रकाश चौटाला तो लोगों के पास सुबह-सुबह चले जाते हैं और लोग इनको हाथ जोड़ कर कहते हैं कि आप सुबह न आया करो, हमारा सारा दिन खराब हो जाता है। धीर पाल जी ने एक बात कही कि हम कांग्रेस के साथ नहीं मिल रहे जबकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कांग्रेस के साथ मिलकर राजनीति कर रहे हैं, यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है।

श्री वीर पाल सिंह : स्पीकर साहब, मैं फिर कह रहा हूं कि हम कांग्रेस के साथ नहीं मिले हुए। मैंने पहले भी यह बात कही है, यह रिकार्ड में है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

जन-स्वास्थ्य मंत्री (श्री जगन्नाथ) : स्पीकर साहब, चौटाला साहब ने कहा कि 16 फरवरी को देख लेंगे। मैं इनको याद दिलाने के लिए बताना चाहता हूं कि 96 के असैम्बली के चुनाव में इन्होंने मुंडाल गांव में जी०टी० रोड पर कहा था कि तौशाम से बंसी लाल जीत गया तो मैं राजनीति से सन्यास ले लूंगा। इसी प्रकार से इन्होंने झज्जर में कहा कि यदि विकास पार्टी यहां से जीत गई तो मैं सन्यास ले लूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि ये सन्यास लेंगे या नहीं।

शिक्षा मंत्री (श्री राम विलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, जब तक कोई गुरु नहीं होगा तो किसी को सन्यास कैसे मिलेगा। चौधरी भजन लाल और चौटाला साहब को कोई गुरु अपना चेला ही बनाने के लिए तैयार नहीं है और जब तक कोई अच्छा गुरु न मिल जाए तो ये सन्यास कैसे लेंगे ? (शोर)

श्रीमती करतार देवी : अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के साथी यहां पर अनर्गल बातें करते हैं और कहते हैं कि हम कांग्रेस वाले किसी से मिले हुए हैं। मैं सदन की जानकारी के लिए यह बताना चाहती हूं कि कांग्रेस का अपना एक इतिहास है, एक प्रोग्राम है। हमारी कांग्रेस पार्टी की कुछ नीतियां हैं और कुछ अपने कार्यक्रम हैं।

श्री राम विलास शर्मा : इसीलिए तो कांग्रेस पार्टी को अब चुनाव के लिए इटली से वोट मांगने के लिए सहारा लेना पड़ा है। (शोर)

श्रीमती करतार देवी : गांधारी भी तो गंधार से आई थी। जब वह भारत में आकर रहने लगी तो उसने भी भारतीय परम्पराओं का पालन किया था। इसी प्रकार से सोनिया गांधी भी स्वर्गीय राजीव गांधी की पत्नी हैं, आपको उनके बारे में ऐसी बात कहना शोभा नहीं देता। (शोर) आज ये भाई चौटाला साहब के नाम पर शोर मचा रहे हैं। जब हमारी सरकार थी तो ये बंसी लाल जी जब विपक्ष में बैठते होते थे तो चौटाला साहब की मदद बार-बार लिया करते थे। अब अगर चौटाला साहब ने कोई अच्छी बात के लिए हमारे से सहयोग मांगा है तो कोई बुरी बात नहीं है। आज आपकी सरकार की बात हो रही है तो यह हर जुबान पर है कि इतने आदमी गोलियों से मारे गए हैं। *******

श्री अध्यक्ष : यह रिकार्ड न किया जाये।

नियम 121 के अधीन प्रस्ताव (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker : Question is-

That the provisions of Rule 228, 230, 230-B and 260-A of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly in-so-far as they relate to the constitution of the-

(i) Committee on Public Accounts;

(ii) Committee on Estimates;

(iii) Committee on Public Undertakings; and

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

(iv) Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes.

for the year 1998-99 be suspended and also

That this House authorises the Speaker, Haryana Vidhan Sabha, to nominate the members of the aforesaid Committees for the year 1998-99, keeping in view the proportionate strength of various parties/ groups in the House.

The motion was carried.

वर्ष 1997-98 के अनुपूरक अनुमान पेश करना

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will present the Supplementary Estimates for the year 1997-98.

Finance Minister (Shri Charan Dass Shorewala) : Sir, I beg to present the Supplementary Estimates for the year 1997-98.

वर्ष 1997-98 के अनुपूरक अनुमानों पर एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट पेश करना

Mr. Speaker : Now, Shri Sat Pal Sangwan, Chairman, Committee on Estimates, will present the Report of the Committee on Estimates on the Supplementary Estimates for the year 1997-98.

Chairman, Committee on Estimates (Shri Sat Pal Sangwan) : Sir, I beg to present the Report of the Committee on Estimates on the Supplementary Estimates for the year 1997-98.

वर्ष 1998-99 (चार मास) का लेखानुदान पेश करना

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will present the Vote-on-Account 1998-99 (for four months i.e. April, May, June and July, 1998).

वित्त मंत्री (श्री चरण दास) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस गरिमामय सदन के समक्ष वर्ष 1998-99 का वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

मैं प्रारम्भ में यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि यह केवल एक अन्तरिम बजट है जो कि आगामी वर्ष के पहले चार मास के लिए राज्य के चालू खर्चे को पूरा करने हेतु लेखानुदान प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। यह इसलिए आवश्यक है, क्योंकि आगामी वर्ष के विकास कार्यों एवं केन्द्रीय सहायता के प्रश्न पर अभी केन्द्रीय योजना आयोग द्वारा विचार किया जाना है। सामान्तया, इन प्रस्तावों पर प्रति वर्ष जनवरी माह में विचार-विमर्श हो जाता है, परन्तु इस वर्ष लोकसभा चुनावों के बाद केन्द्र में नई सरकार स्थापित होने के उपरान्त ही इन प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा। राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता की सही स्थिति योजना आयोग से अनुमोदन के बाद ही मालूम होगी, जिसकी बैठक अगले वित्त वर्ष में होनी सम्भावित है।

[श्री चरण दास]

इसलिए चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों के आधार पर ही केवल चार मास की अवधि के लिए लेखानुदान प्राप्त किया जा रहा है। पूर्ण बजट प्रस्ताव सदन के आगामी सत्र में प्रस्तुत किये जायेंगे। अतः कुछ जरूरी किस्म के खर्चों के लिए पर्याप्त वित्तीय प्रावधान करने हेतु उचित सावधानी बरती गई है जैसे खाद्यान्न प्राप्ति, मलेरिया तथा डेंगू से बचाव कार्य, पांचवें वेतन आयोग की सिफारशों को लागू करने सम्बन्धी खर्च तथा ऊर्जा क्षेत्र में ढाँचागत परिवर्तन सम्बन्धित खर्च।

माननीय सदस्यगण, इस अवसर पर राज्य के सामाजिक व आर्थिक सूचकों का विस्तारपूर्वक पुनर्विलोकन करना आवश्यक हो जाता है क्योंकि राज्य के विकास कार्यक्रमों की सही जानकारी ऐसे मूल्यांकन के दृष्टिगत ही की जा सकती है। इसलिए, मैं राज्य की सामान्य आर्थिक स्थिति की समीक्षा करना चाहूँगा।

हरियाणा का वर्ष 1997-98 का आर्थिक सर्वेक्षण जो इस गरिमामय सदन में प्रस्तुत किया गया है, चालू वर्ष के दौरान राज्य की सम्पूर्ण आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालता है। यह एक प्रसन्नता का विषय है कि राज्य की अर्थ-व्यवस्था, जिसे 1995-96 के दौरान आई अभूतपूर्व बाढ़ के कारण गहरा आघात पहुँचा था, वर्तमान सरकार के अथक प्रयासों एवं रचनात्मक सोच के परिणामस्वरूप, नई शक्ति व स्फूर्ति के साथ पुनः उभरी है। राज्य की सकल आय, जो 1995-96 में 7409.23 करोड़ रुपये थी, 1996-97 में 9.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 8134.57 करोड़ रुपये हो गई है। वर्ष 1996-97 के दौरान प्राथमिक क्षेत्र में अंशदान 7 प्रतिशत बढ़ गया है और माध्यमिक व तृतीयक क्षेत्र के अंशदान में क्रमशः 11.7 तथा 9.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इससे प्रतीत होता है कि कृषि क्षेत्र की, अभी भी राज्य की अर्थ-व्यवस्था में प्राथमिकता बरकरार है क्योंकि इसका कुल सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 42 प्रतिशत अंशदान है। वर्ष 1980-81 के स्थिर-मूल्यों के अनुसार प्रति व्यक्ति आय वर्ष 1995-96 के 3668 रुपये के मुकाबले वर्ष 1996-97 में 3956 रुपये हो गई है। अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता सूचकांक मार्च, 1996 में 319 से 10 प्रतिशत बढ़कर मार्च, 1997 में 351 हो गया। यह पुनः अक्तूबर, 1997 में 4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 365 हो गया है।

महोदय, अब मैं वर्ष 1997-98 की वार्षिक योजना की प्रगति माननीय उपस्थित सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ, जो काफी प्रसन्नताजनक तथा उत्साह-वर्धक है। योजना आयोग ने वर्ष 1997-98 के लिए राज्य हेतू 1575 करोड़ रुपये का योजना परिव्यय अनुमोदित किया था जिसे बाद में संशोधित करके 1576.04 करोड़ रुपये कर दिया गया। इस योजना के लिए राज्य द्वारा अपने संसाधनों से 903.28 करोड़ रुपये तथा केन्द्रीय सहायता से 672.76 करोड़ रुपये जुटाये जाने हैं। केन्द्रीय सहायता राशि में 232.14 करोड़ रुपये साधारणतःमिलने वाली सहायता तथा 343.96 करोड़ रुपये की राशि विदेशी सहायता परियोजनाओं के लिए शामिल है, परन्तु योजना संसाधनों की उपलब्धता मुख्यतया विदेशी सहायता में कमी आने के कारण कम हो गई। यह एक हर्ष का विषय है कि मद्य-निषेध के कारण आबकारी राजस्व में हुए भारी घाटे के बावजूद चालू वर्ष के लिए संशोधित योजना परिव्यय 1400 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया है, जो वर्ष 1996-97 के 1247.41 करोड़ रुपये के खर्च से 12.02 प्रतिशत अधिक है। यह सब सरकार द्वारा सुदृढ़ वित्तीय अनुशासन लागू करने तथा राजस्व की चोरी को रोकने के कारण अच्छी वसूलियां प्राप्त करने, विभिन्न कर तथा गैर कर उपायों द्वारा अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने के लिए किए गए अथक प्रयासों के कारण सम्भव हो पाया है। लघु बचत अभियान के तेजीकरण के परिणामस्वरूप 40 करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण प्राप्त हुआ। चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय

करों से राज्य को 60 करोड़ रुपये अधिक प्राप्त हुए। राज्य सरकार लोगों के पूर्ण सहयोग के कारण ही विकास की गति को बढ़ाने में सफल हो पाई है।

अब, मैं राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष के दौरान प्राप्त की गई मुख्य उपलब्धियों पर संक्षिप्त प्रकाश डालना चाहूंगा।

मद्य-निषेध : शान्ति एवं समृद्धि का इन्द्रधनुष

माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि विभिन्न सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक संगठनों तथा विशेष तौर पर महिलाओं, जिन्होंने इस बारे में एक राज्यव्यापी आन्दोलन किया था, की निरन्तर मांग पर वर्तमान सरकार ने कार्यभार संभालते ही, 1 जुलाई, 1996 से राज्य में पूर्ण मद्य-निषेध लागू करने के लिए एक क्रान्तिकारी निर्णय लिया था।

कानून का उल्लंघन करने वालों को पकड़ने के लिए मौजूदा अधिनियम में विशेष संशोधन किये गये हैं। राज्य में शराब की तस्करी को रोकने के लिए पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 की धारा 3, 14, 78 व 79 में संशोधन करते हुए राज्य में 19 नवम्बर, 1997 को एक अध्यादेश जारी किया गया है जिसके द्वारा शराब की तस्करी में संलिप्त वाहनों व अन्य सम्पत्तियों को जब्त करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। प्रत्येक जिले में एक डौग स्क्वॉड तैयार किया जा रहा है। शराबी व्यक्तियों की लत छुड़ाने के लिए 8 नशामुक्ति केन्द्र चालू किये गये हैं तथा उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व महाविद्यालय स्तरीय सभी कक्षाओं में मद्य-निषेध पर आधारित पाठ्यक्रम लागू किया गया है।

कानून तोड़ने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध एक सुनियोजित अभियान तथा लोगों के सहयोग के परिणामस्वरूप मद्य-निषेध सामाजिक जीवन में एक रचनात्मक परिवर्तन लाने वाला तथा लोगों को एक स्वच्छ तथा अधिक आरामदायक जीवन देने वाला आन्दोलन बन गया है। गुण्डातत्त्वों द्वारा पियक्कड़ व्यवहार का प्रदर्शन करना अब एक अतीत की बात हो गई है। अपराधों की संख्या में भी गिरावट आई है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर को नया रूप देने की दिशा में बढ़ते कदम

लोगों को चौबीस घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करना राज्य सरकार का दृढ़ संकल्प एवं चिन्ता का मुख्य विषय है। ऊर्जा क्षेत्र के ढाँचे को नया रूप देने के लिए राज्य सरकार ने विश्व बैंक से 600 मिलियन अमरीकी डॉलर (लगभग 2400 करोड़ रुपये) की ऋण-शृंखला बारे बातचीत की है जिसका अनुमोदन 15 जनवरी, 1998 को बैंक के निर्देशों द्वारा कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य में बिजली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अनेक परियोजनाएं अन्तिम चरण में हैं। माननीय सदस्यों को अवगत होगा कि राज्य सरकार कृषि क्षेत्र को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है जिसके लिए हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड द्वारा कृषि क्षेत्र को सस्ती दरों पर बिजली दिए जाने के एवज़ में राज्य सरकार ने चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमानों में 679.94 करोड़ रुपये बतौर ऊर्जा सबसिडी व 317.45 करोड़ रुपये योजना व गैर योजना सहायता के तौर पर उपलब्ध कराए हैं।

यातायात में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए लोगों को बेहतर सड़क-संरचना मुहैया कराना भी सरकार का प्रयास रहा है, जिसके लिए 627 किलोमीटर राज्य-राजमार्ग और शेष राज्य-राजमार्गों के अनुरक्षण हेतु राज्य सरकार ने 1408 करोड़ रुपये के कर्ज़ हेतु विश्व बैंक से बातचीत शुरू की है, जिसके लिए प्रारम्भिक परियोजना मूल्यांकन पूरा हो चुका है। राष्ट्रीय राजमार्ग नं० 1 को सुदृढ़ बनाने व चार-मार्गी

[श्री चरण दास]

बनाने का कार्य अधिकतर हिस्से में किया जा चुका है। बल्लभगढ़ से उत्तर प्रदेश सीमा तक राष्ट्रीय राजमार्ग नं० 2 को सुदृढ़ बनाने तथा चार-मार्गी बनाने का कार्य एशियन डिवेलपमेंट बैंक की सहायता से 108 करोड़ रुपये की लागत से पूरा किया जा चुका है।

राज्य सरकार ने इस तथ्य के दृष्टिगत कि सिंचाई, कृषि क्षेत्र की जीवन-रेखा है, विश्व बैंक से सहायता प्राप्त जल संसाधन समेकन परियोजना, जो भारत में अपने प्रकार की पहली परियोजना है, के अन्तर्गत सिंचाई की वर्तमान आधारभूत संरचना में सुधार लाने के साथ-साथ नई माइनरों, ड्रेनों और बैराजों के निर्माण की प्रक्रिया को तेज़ करने पर विशेष बल दिया है। इस परियोजना के अन्तर्गत 1858 करोड़ रुपये की लागत से वर्तमान सिंचाई ढांचे की मरम्मत, नहर-प्रणाली का आधुनिकीकरण व हथनीकुण्ड बैराज का निर्माण किया जा रहा है और उप-सतही ड्रेनेज-प्रणाली की अग्रणी योजना कार्यान्वित की जा रही है। आप को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि वर्तमान ड्रेनों की गाद निकालने और नई ड्रेनेज-प्रणाली का निर्माण करने के लिए सरकार द्वारा किए गए विशेष प्रयासों के फलस्वरूप ही राज्य में चालू वर्ष के दौरान कहीं कोई विशेष बाढ़ नहीं आई। अधिकतर ड्रेनों, जैसे कि डाइवर्शन ड्रेन नं० 8 तथा मुख्य ड्रेन नं० 6, नाई नाला, पुण्डरी ड्रेन, हिसार ड्रेन, कैथल ड्रेन तथा कई अन्य ड्रेनों पर कार्य पूरा हो चुका है। सिंचाई चैनलों की घास निकालने के लिए भी कदम उठाये गये हैं ताकि नहरों की टेलों तक पानी पहुँच सके।

मनुष्यों तथा पशुओं दोनों के लिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना भी राज्य सरकार की प्रमुख वचनबद्धता है। चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने केन्द्रीय सहायता से 100 गाँवों में पेयजल सप्लाई को बढ़ाकर प्रतिदिन 70 लिटर प्रति व्यक्ति करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिनमें से 30 गांवों में पेयजल सप्लाई पहले ही बढ़ा दी गई है। राज्य सरकार ने पांच हज़ार से अधिक की आबादी वाले 405 गाँवों में पेयजल सप्लाई बढ़ा कर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन 110 लिटर करने के लिए भी एक विशेष योजना शुरू की है, जिसके परिणाम स्वरूप इन गांवों में समुचित सीवरेज प्रणाली स्थापित करना सुगम हो जाएगा और ये गांव वास्तव में छोटी नगरपालिकाओं के समकक्ष हो जाएंगे जिससे ग्रामीण-क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा। राज्य सरकार ने सभी गांवों तथा शहरों को सुनिश्चित तथा स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के बाद अब ऐसी ढाणियों को भी 31 मार्च, 1998 तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य अपने हाथ में ले लिया है, जिनकी आबादी 100 या 100 से अधिक है। 232.20 करोड़ रुपये की यमुना कार्य परियोजना को, जिसके लिये भारत सरकार द्वारा हिस्सेदारी के आधार पर धन उपलब्ध कराया जा रहा था, अब शत-प्रतिशत केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना में तबदील कर दिया गया है, इससे राज्य के 12 प्रमुख शहरों में समुचित सीवरेज तथा ड्रेनेज प्रणाली स्थापित होगी।

कृषि एवं सम्बद्ध गति विधियाँ : राज्य की मुख्य प्राथमिकता

चूँकि कृषि लोगों का मुख्य पेशा है, इसलिए सरकार ने कृषि क्षेत्र को लाभ पहुँचाने वाली योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया है। चालू वर्ष के लिए निर्धारित 115 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य को गत सितम्बर मास के अन्त में और गत अक्तूबर मास के शुरू में तेज़ हवाओं के साथ हुई बेमौसमी वर्षा के बावजूद पूरा किए जाने की सम्भावना है। बागवानी विभाग ने खुम्भी के उत्पादन को काफी बढ़ावा दिया है। वर्ष 1997-98 के दौरान 2700 टन खुम्भी का रिकार्ड उत्पादन होने की सम्भावना है। फूलों की खेती के अन्तर्गत क्षेत्र भी चालू वर्ष के अन्त तक बढ़कर 2000 हैक्टेयर हो

जाएगा। किसानों को उच्च कोटी की कृषि सामग्री उपलब्ध कराने के लिए समुचित प्रबन्ध किए गए हैं। किसानों को वितरित करने के लिए खरीफ, 1997 के लिए विभिन्न फसलों के 0.8 लाख क्विंटल प्रमाणित बीजों तथा रबी मौसम के लिए 3.75 लाख क्विंटल प्रमाणित बीजों की व्यवस्था की गई है। धान की फसल को हानिकारक खरपतवारों से बचाने के लिए 6.09 लाख लिटर खरपतवार नाशक दवाइयां वितरित की गई हैं। कृषि विभाग समेकित वॉटरशैड विकास (पहाड़ी) परियोजना के अन्तर्गत जिला अम्बाला, पंचकूला और यमुनानगर के अर्ध-पर्वतीय क्षेत्रों को विश्व-बैंक की सहायता से वॉटरशैड के आधार पर विकसित कर रहा है। "समतल उप-सतही ड्रेनेज प्रणाली" की तकनीक से 2,000 हैक्टेयर सेमग्रस्त भूमि को सुधारने के लिए डच सरकार की सहायता से एक विशेष कल्लर भूमि-सुधार योजना शुरू की गई है ताकि इस बंजर भूमि पर पुनः कृषि उत्पादन किया जा सके। राज्य में कृषि शिक्षा की गुणवत्ता एवं प्रासंगिकता में सुधार लाने, स्टाफ की कार्यकुशलता बढ़ाने और कृषि से जुड़े मानव संसाधनों की क्षमता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विश्व-बैंक की सहायता से कृषि मानव संसाधन विकास परियोजना शुरू की गई है जिस पर 53.74 करोड़ रुपये खर्च होने की सम्भावना है।

11.00 बजे | रबी 1997-98 के दौरान राज्य तथा इसकी खरीद एजैंसियों ने केन्द्रीय अन्न-भण्डार में 22.90 लाख टन गेहूँ दिया, जबकि गत वर्ष केन्द्रीय अन्न-भण्डार को 20.60 लाख टन गेहूँ दिया गया था। धान के चालू खरीद मौसम के दौरान 9 लाख टन चावल की रिकार्ड खरीद होने की सम्भावना है।

वृक्षारोपण कृषि का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। राज्य ने लोगों के सहयोग से फार्म-वानिकी को बढ़ावा देकर तथा पंचायती बंजर भूमि और रेत के टीलों पर भारी संख्या में वृक्षारोपण करके प्रदेश में वनों के अधीन क्षेत्र को बढ़ाकर, कुल क्षेत्र का 8 प्रतिशत करने में सफलता प्राप्त की है। वर्ष 1997-98 के दौरान 18 हजार हैक्टेयर क्षेत्र पर वृक्षारोपण करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य योजनाओं के अन्तर्गत 297 लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है। इस गतिविधि के फलस्वरूप चालू वर्ष के दौरान 27.26 लाख श्रम-दिवसों का रोज़गार उपलब्ध होने की सम्भावना है।

पशुपालन को कृषि का अभिन्न अंग बनाने के लिए सरकार तथा लोगों द्वारा किए गए सतत प्रयासों के फलस्वरूप राज्य में दूध की उपलभ्यता 620 ग्राम प्रति-व्यक्ति प्रतिदिन है और प्रदेश का इस दृष्टि से देश मे दूसरा स्थान है। राज्य 2217 पशु संस्थाओं के नेटवर्क द्वारा अपने पशुधन का विभिन्न संक्रामक तथा गैर-संक्रामक रोगों से बचाव कर रहा है।

सहकारी आन्दोलन : सहभागी प्रबन्धन द्वारा आर्थिक पुनरुत्थान

माननीय सदस्य इस बात पर सहमत होंगे की हरियाणा में सहकारी आन्दोलन ने प्रारम्भ से लेकर अब तक लम्बा सफर तय किया है। राज्य में सहकारी समितियों की सदस्यता वर्ष 1966-67 में 9.23 लाख से बढ़कर वर्ष 1996-97 में 47.36 लाख हो गई है। इनकी कार्यपूंजी भी चालू वर्ष के दौरान 68.90 करोड़ रुपये से बढ़कर 78.30 करोड़ रुपये हो गई है।

वर्ष 1997-98 के दौरान किसानों तथा ग्रामीण दस्तकारों को 1220.02 करोड़ रुपये के फसली कर्जे दिए गए जबकि गत वर्ष 922.78 करोड़ रुपये के फसली कर्जे दिए गए थे। चालू वर्ष के दौरान किसानों को दिए जाने वाले ऋणों पर ब्याज दर दो प्रतिशत घटाकर 16 प्रतिशत से 14 प्रतिशत कर दी गई है, जिससे किसानों को हरियाणा राज्य सहकारी बैंकों से आकर्षक शर्तों पर ऋण प्राप्त करने में मदद मिलेगी। राज्य सरकार गन्ना उत्पादकों की समस्याओं के प्रति भी संवेदनशील है। चालू वर्ष के दौरान

[श्री चरण दास]

सरकार ने 10 सहकारी चीनी मिलों को कार्य पूंजी के रूप में 218 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं ताकि इनकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि की जा सके। सरकार ने गन्ने के खरीद मूल्य में भी काफ़ी वृद्धि की है। अगेती क़िस्म की दर 80 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 82 रुपये प्रति क्विंटल, मध्य में पकने वाली क़िस्म की दर 78 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति क्विंटल तथा सामान्य किस्म की दर 76 रुपये से बढ़ाकर 78 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है।

औद्योगिक विकास : सन्तुलित विकास तथा निजी भागीदारी द्वारा नए कीर्तिमान

सड़कों तथा रेलगाड़ियों जैसी सुव्यवस्थित ढाँचागत सुविधाओं, पानी और बिजली की उपलब्धता, सुस्थापित औद्योगिक सम्पदाओं, सुदृढ़ बैंकिंग सुविधाओं, भरोसेमन्द संचार-व्यवस्था तथा तकनीकी रूप से प्रशिक्षित जन-शक्ति के कारण हरियाणा में औद्योगिक परिदृश्य ने वर्तमान सरकार की देख-रेख में नई गति प्राप्त की है। न केवल बड़े तथा मध्यम दर्जे के उद्योगों की संख्या 1966 में 162 से बढ़कर आज 927 हो गई है, अपितु लघु उद्योग क्षेत्र में भी 1.40 लाख से भी अधिक औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुई हैं, जिनमें आज दस लाख से भी अधिक व्यक्ति काम करते हैं। इसके अतिरिक्त वार्षिक निर्यात भी पांच वर्ष पूर्व के 438 करोड़ रुपये से बढ़कर चालू वर्ष के दौरान 2400 करोड़ रुपये हो गया है, जोकि एक रिकार्ड है।

राज्य सरकार ने प्रदेश का सन्तुलित औद्योगिक विकास करने और पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास दर तेज़ करने पर विशेष बल देने के लिए हाल ही में एक नई उद्योग नीति की घोषणा की है जिसका उद्देश्य उद्योगों के विकास के लिए बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना है। नियमों और प्रक्रियाओं के सरल बनाना, लालफीताशाही समाप्त करना, इस नई उद्योग नीति की प्रमुख विशेषताएं हैं। औद्योगिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना इस नई उद्योग नीति के प्रमुख आधार हैं। मानेसर, जिला गुड़गांव में औद्योगिक मॉडल टॉऊनशिप परियोजना को पुनः शुरू करना औद्योगिक क्षेत्र में वर्तमान सरकार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस परियोजना का उद्देश्य उद्योगों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की औद्योगिक इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं की स्थापना के लिए 1730 एकड़ भूमि का विकास करना है। हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम कुण्डली में एक प्रतिष्ठित निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क तथा ज़िला अम्बाला के साहा में एक औद्योगिक विकास केन्द्र विकसित कर रहा है।

नागरिक प्रशासन : स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करना

स्वशासी नागरिक निकायों के विकास के लिए स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करना भी हरियाणा जैसे कल्याणकारी राज्य की एक जिम्मेदारी है। अतः चालू वर्ष के दौरान राज्य द्वारा स्थानीय निकायों के विकास पर उनके अपने संसाधनों के अतिरिक्त 33.98 करोड़ रुपये खर्च करने का अनुमान है। शहरी क्षेत्रों के निवासियों की जीवन दशा में सुधार लाने के लिए उन्हें पेयजल-सप्लाई, सामुदायिक स्नानगृह और शौचालय, गलियों में प्रकाश-व्यवस्था तथा मल-निकास और बाढ़ जल-निकास जैसी बुनियादी सुविधाएं देने में शहरी गन्दी बस्ती पर्यावरण सुधार स्कीम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। चालू वित्त वर्ष के दौरान इस स्कीम के लिए कुल 7.80 करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है तथा 99,625 गन्दी बस्ती बासियों को इस स्कीम का लाभ मिलने की सम्भावना है।

राज्य में छोटे तथा मध्यम दर्जे के नगरों के एकीकृत विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित

एक योजना शुरू की गई है ताकि छोटे तथा मध्यम दर्जे के नगरों का विकास करके उनके आर्थिक तथा भौतिक ढांचे में सुधार लाया जा सके तथा बढ़े हुए निवेश द्वारा बड़े नगरों में जनसंख्या के बढ़ते हुए दबाव को रोका जा सके। गन्दी बस्ती क्षेत्रों के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता से एक विशेष कार्यक्रम भी शुरू किया गया है, जिस पर चालू वर्ष के दौरान 4.69 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा रही है।

10वें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश किये गये अनुदानों में से चालू वित्त वर्ष के दौरान नगरपालिकाओं को 103.75 लाख रुपये की राशि दी गई है। राज्य ने 1-12-97 से स्वर्ण जयन्ती शहरी रोज़गार योजना नाम की केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक नई योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य स्व-रोज़गार के माध्यम से शहरी बेरोज़गार अथवा कम रोज़गार वाले व्यक्तियों को लाभदायक रोज़गार देना है। स्वः रोज़गार के अन्तर्गत शहरी निर्धन महिलाओं की सहायता के लिए शहरी क्षेत्रों में महिला तथा बाल विकास नामक एक कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए लाभदायक रोज़गार जुटाना है।

ग्रामीण विकास : ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों के लिये आशा का सवेरा

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले निर्धन व्यक्तियों के उत्थान हेतु राज्य में विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 5455 लाभानुभोगियों को लाभ देकर नवम्बर, 1997 तक 4.41 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों को विकास के उद्देश्य से डवाकरा कार्यक्रम के अन्तर्गत आय जुटाने वाले सामूहिक क्रिया-कलापों के माध्यम से ग्रामीण महिला-समूहों के लिए लाभदायक रोजगार जुटाया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा राज्य के विभिन्न सूखाग्रस्त भागों में सूखे की रोकथाम व पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए मरुस्थल विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके द्वारा भूमि एवं नमी संरक्षण, भूमि समतल कार्यक्रम, शुष्क-भूमि की जुताई, जल संसाधन विकास, वृक्षारोपण व चरागाह विकास कार्यक्रमों को एकीकृत रूप में वाटरशैड आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है।

बेरोजगार तथा कम रोजगार वाले ग्रामीण लोगों के लिए लाभप्रद रोजगार जुटाने के लिए जवाहर रोजगार योजना लागू की जा रही है। इस परियोजना के अन्तर्गत नवम्बर, 1997 तक 10.68 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं तथा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 8.83 लाख श्रम दिवस वतौर रोजगार जुटाए गए हैं। इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत नवम्बर, 1997 तक 1955 मकानों का निर्माण किया गया है तथा 1039 अतिरिक्त मकानों का निर्माण-कार्य प्रगति पर है।

कृषि क्षेत्र में मन्दी के मौसम के दौरान लाभप्रद रोजगार प्रदान करने के विचार से राज्य में रोजगार आश्वासन योजना आरम्भ की गई है। चालू वर्ष के दौरान बाकी बचे हुए खण्डों में भी इस स्कीम का विस्तार किया गया है। अब राज्य के सभी खण्ड रोज़गार आश्वासन योजना के अन्तर्गत आ गए हैं। नवम्बर, 1997 के अन्त तक इस परियोजना के अन्तर्गत 36.95 करोड़ रुपये की राशि ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करवाई गई है।

गंगा कल्याण योजना एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रामीण योजना है, जो गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लघु तथा सीमान्त किसानों के समूहों तथा व्यक्तियों को नलकूप तथा पीर-ट्यूबवैल सुलभ करवाने के लिए 1-2-1997 से आरम्भ की गई है। चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य में इस स्कीम के कार्यान्वयन हेतु 1.67 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं।

[श्री चरण दास]

परिवहन : जन-जीवन का संचार माध्यम

1739 मार्गों पर चल रही हरियाणा राज्य परिवहन की 3770 बसों द्वारा प्रतिदिन 15.89 लाख यात्री यात्रा करते हैं और ये बसें प्रतिदिन 11.26 लाख कि०मी० रास्ता तय करती हैं।

चालू वित्त वर्ष के दौरान असन्ध, रतिया और जुलाना में आधुनिक बस-अड्डों का निर्माण पूरा करके उन्हें चालू कर दिया गया है इसके अतिरिक्त समालखा का बस-अड्डा मुकम्मल हो चुका है और अटेली तथा चरखी-दादरी के बस-अड्डों का निर्माण-कार्य पूरा होने वाला है। राजौंद के बस-अड्डे और रोहतक तथा अम्बाला के नये बस-अड्डे निर्माणाधीन हैं। भिवानी में बस-अड्डा बनाने के लिए भूमि अधिगृहीत की गई है और लोहारू के बस-अड्डे के लिये भूमि-अधिग्रहण करने सम्बन्धी कार्यवाही पूरी हो चुकी है। कलायत, भादरा, रादौर, बलदेव नगर (अम्बाला शहर) और कैथल के बस-अड्डों के लिये भूमि अधिग्रहण करने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

मैक्सी-कैब वाहनों को अप्राधिकृत तौर पर चलाने पर अंकुश लगाने और राजस्व की चोरी को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा 31 अक्तूबर, 1997 तक 2118 मैक्सी-कैब वाहनों को प्राधिकृत मार्गों पर चलाने हेतु कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट दिये गये हैं।

चालू वित्त वर्ष के दौरान 567 पुरानी बसों को 51.30 करोड़ रुपये के परिव्यय से बदला जा रहा है।

स्वास्थ्य : "सब के लिये स्वास्थ्य" के लक्ष्य की ओर अग्रसर

2299 उप-केन्द्रों, 400 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 64 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और 48 अस्पतालों के नेटवर्क द्वारा स्वास्थ्य विभाग बेहतर उपकरण, प्रशिक्षित कर्मचारीगण और बेहतर दवाइयां मुहैया करवा कर राज्य में स्वास्थ्य के ढांचे को आधुनिक बनाने का कार्य कर रहा है।

माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है, जिसमें पी०एच०सी० स्तर पर दंत चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की गई हैं। इसी प्रकार, हरियाणा देश का ऐसा प्रथम राज्य है, जिसमें हेपाटाइटिस "बी" के टीकाकरण को प्रतिरक्षण कार्यक्रम का एक हिस्सा बना दिया गया है। मलेरिया और डेंगू की विभीषिका को नियन्त्रित कर लिया गया है। संतोष का विषय है कि इस वर्ष मलेरिया और डेंगू के कारण किसी भी व्यक्ति की मृत्यु की सूचना प्राप्त नहीं हुई।

भारत सरकार ने विश्व-बैंक और अन्य सहायता देने वाली एजैन्सियों की मदद से हरियाणा राज्य में पांच वर्षों अर्थात् 1997-98 से 2001-2002 तक प्रजनन बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम को अनुमोदित किया है। इस कार्यक्रम पर 131.17 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जननक्षमता व माता तथा बच्चे के स्वास्थ्य की देखभाल को प्रजनन तथा स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ना है। इस प्रजनन बाल स्वास्थ्य परियोजना से माता तथा बच्चे की मृत्यु दर और जनसंख्या वृद्धि में उल्लेखनीय कमी होने की सम्भावना है।

सरकार ने पी०जी०आई० एम०एस० रोहतक में आपातकालीन सेवाओं में सुधार लाने के लिये प्रयास किया है तथा नये उपकरणों की खरीद के लिए इस संस्थान के बजट में भी वृद्धि की है।

शिक्षा : मूल्यों पर आधारित सामाजिक-ढाँचा-निर्माण

सामाजिक जीवन के गुणात्मक पहलू में सुधार लाने और आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए मूल्यों पर आधारित सामाजिक ढाँचा तैयार करने हेतु समाज के सभी वर्गों के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने की जिम्मेदारी सरकार ने स्वयं अपने ऊपर ली है।

चालू वर्ष के दौरान 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों को दाखिल करने के लिए स्थानीय निकायों के सक्रिय योगदान से एक विशेष दाखिला अभियान शुरू किया गया। इस अभियान के परिणामस्वरूप,बच्चों का दाखिला वर्ष 1991-92 के 21.66 लाख से बढ़ कर वर्ष 1996-97 में 24.19 लाख हो गया, जबकि आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 24.18 लाख बच्चों को दाखिल करने का लक्ष्य रखा गया था। सरकार द्वारा किया गया एक अन्य महत्त्वपूर्ण कार्य जिला गुड़गांव के मेवात क्षेत्र के लिए अध्यापकों के 500 नये पद स्वीकृत करना व विशेष अभियान के माध्यम से 35,000 बच्चों को दाखिल करना है। बच्चों, विशेषतया अनुसूचित जातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों की लड़कियों को दाखिल करने और विद्यालय छोड़ कर न जाने देने के लिए नि:शुल्क वर्दियां, उपस्थिति पुरस्कार, मुफ्त लेखन सामग्री, नि:शुल्क पाठ्य-पुस्तकें और घुमन्तु कबीलों के बच्चों को विशेष प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं। राज्य के सभी 111 सामुदायिक खण्डों एवं शहरी क्षेत्रों में भी मध्याह्न भोजन स्कीम शुरू की जा चुकी है।

विश्व-बैंक सहायता प्राप्त "जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना" जो पहले केवल जींद, हिसार और सिरसा जिलों में चालू थी, अब गुड़गांव, महेन्द्रगढ़ और भिवानी जिलों में भी शुरू की जा रही है। राज्य सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान कुल 375 विद्यालयों को (112 प्राथमिक, 120 माध्यमिक व 143 उच्च विद्यालय) अपग्रेड किया है। उच्चतर शिक्षा के अन्तर्गत 4 गैर-सरकारी महाविद्यालय खोलने की अनुमति दी गई और अम्बाला छावनी, बोंद कलां व कृष्ण नगर (जिला नारनौल) में नये राजकीय महाविद्यालय खोले गये। महेन्द्रगढ़ कॉलेज की कन्या शाखा को पूर्ण कन्या महाविद्यालय का दर्जा दिया गया और नांगल चौधरी के गैर-सरकारी महाविद्यालय को सरकार द्वारा अपने अधिकार में ले लिया गया है।

समाज कल्याण : कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत को मूर्तरूप देता हुआ

राज्य सरकार ने एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए महिलाओं, बच्चों, वृद्धों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, विमुक्त जातियों और पिछड़े वर्गों के सामाजिक व आर्थिक स्तर को विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से ऊंचा उठाने पर विशेष बल दिया है।

राज्य में महिलाओं के विकास के लिए पोषण तथा अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं जुटाने के लिए विदेशी सहायता मांगी गई है। एकीकृत महिला सशक्तता एवं विकास परियोजना के अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि से शत-प्रतिशत सहायता ली गई है ताकि महेन्द्रगढ़ जिले और रिवाड़ी जिले के 70 गांवों की महिलाओं को लाभ मिल सके। गुड़गांव जिले के सोहना, नूह व फरूखनगर खण्डों में भी इस परियोजना को लागू कर दिया गया है। इस के लिये जर्मन गणतन्त्र संघ द्वारा लगभग 700 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जा रही है।

हमारा राज्य समाज के वृद्ध, निराश्रित और अभावग्रस्त वर्गों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन स्कीम के अन्तर्गत, 10 लाख लाभानुभोगियों को प्रत्येक मास की 7 तारीख तक पेंशन वितरित की जा रही है, जो कि वर्तमान सरकार

[श्री चरण दास]

का मुख्य वादा था। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए नई योजनाओं, जैसे छात्रवृत्तियां, बेरोजगारी भत्ता, विकलांगों के लिए निःशुल्क उपकरण आदि कार्यान्वयन किया जा रहा है।

राज्य, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्ग के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिए पूर्णतया वचनबद्ध है। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को विभिन्न स्तरों पर छात्रवृत्तियां, शिक्षण शुल्क से छूट, बोर्ड व विश्वविद्यालय के परीक्षा शुल्क का रिफण्ड, लेखन-सामग्री की खरीद के लिए अनुदान, विज्ञान, गणित तथा अंग्रेजी विषयों में विशेष शिक्षण व्यवस्था एवं पुस्तकों आदि की खरीद के लिए बिना ब्याज के कर्जे आदि की सहायता दी जा रही है। इनमें से कुछ योजनाओं का लाभ पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को भी मिल रहा है। राज्य में हरिजन बस्तियों के पर्यावरण में सुधार लाने के लिए कई योजनाओं पर कार्य चल रहा है। इसके अतिरिक्त हरिजन परिवारों के आर्थिक उत्थान के लिए कई योजनाएं, जैसे कि विधवाओं और कन्याओं के लिए सिलाई प्रशिक्षण, विद्यार्थियों को छात्रावास की सुविधाएं, अत्याचार के शिकार व्यक्ति को आर्थिक राहत, अन्तर्जातीय विवाह के लिए प्रोत्साहन राशि व हरिजन विधवाओं की बेटियों के विवाह के लिए अनुदान, कार्यान्वित की जा रही हैं।

हरियाणा पर्यटन : घर से दूर एक घर

हरियाणा पर्यटन के सुन्दर ढंग से सजाए गए भू-दृश्य, उच्च कोटि की वस्तुकला, रंगा-रंग सांस्कृतिक उत्सव, लावण्य एवं आराम का एक बहुरंगी चित्र प्रस्तुत करते हैं। 44 पर्यटन केन्द्रों से सुसज्जित हरियाणा पर्यटन अपनी कई कल्पनात्मक पर्यटन योजनाओं जैसे कि राई में "एथनिक इंडिया" परियोजना तथा बल्लभगढ़ में राजा माहर सिंह महल में हैरिटेज पर्यटन आदि के माध्यम से नई दिशाओं में अपने पंख फैला रहा है।

राज्य सरकार ने नीति भागीदारी के माध्यम से पर्यटन को प्रोत्साहन देने की नई नीति की घोषणा की है। इस नीति के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के उद्यमकर्त्ताओं को पर्यटन विकास हेतु 33 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर भूमि दी जाएगी।

चालू वर्ष के दौरान हरियाणा पर्यटन ने 15 नवम्बर से 24 नवम्बर तक दूसरे कार्तिक मेले का आयोजन करके सांस्कृतिक पर्यटन को भी प्रोत्साहन दिया है। इस मेले में 80,000 पर्यटकों ने भाग लिया।

सरकारी कर्मचारियों का कल्याण : एक उदार नज़रिया

राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के कल्याण के प्रति सदैव चिन्तित रही है और उन्हें वेतन, भत्ते, बोनस तथा अन्य राहत केन्द्रीय सरकार की तर्ज पर देती रही है। पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार द्वारा की गई घोषणा के अन्तर्गत हरियाणा राज्य के कर्मचारियों को संशोधित वेतनमानों के लाभ दिनांक 1-1-96 से दे दिए गए हैं। कर्मचारी, जनवरी, 1998 का वेतन फरवरी, 1998 से संशोधित वेतनमानों में ही प्राप्त करेंगे। इन वेतनमानों के कारण कर्मचारियों का बकाया उन के सामान्य भविष्य निधि खातों में जमा किया जाएगा। इस प्रकार राज्य को लगभग 950 करोड़ रुपये के बकायों का अतिरिक्त भुगतान तथा 500 करोड़ रुपये का वार्षिक अतिरिक्त मकद भुगतान करना होगा। मुझे आशा है कि संशोधित वेतनमानों का लाभ देने से कर्मचारियों में राज्य के कल्याण के प्रति और अधिक समर्पण भाव, उत्साह व दृढ़ संकल्प जागृत होगा।

सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में वर्तमान सरकार की उपलब्धियों से सम्बन्धित इस संक्षिप्त पृष्ठभूमि के साथ मैं आगामी वित्त वर्ष के प्रथम चार मास अर्थात् अप्रैल से जुलाई, 1998 तक के लेखानुदान इस गरिमामय सदन के सम्मुख स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करता हूँ।

जय हिन्द !

Mr. Speaker : Now, the House is adjourned till 2.00 P.M. today.

*11.32 Hours (The Sabha then *adjourned till 2.00 P.M. on Tuesday, the 20th January, 1998.)

30001—H.V.S.—H.G.P. Chd.